



# द रीव टाइम्स

The RIEV Times

हिमाचल, वर्ष 2, अंक 35/ पृष्ठ: 16

मूल्य: ₹ 25/-

[www.therievtimes.com](http://www.therievtimes.com)

All our Thoughts and words travel in the cosmos and their impact on us is directly proportional -Dr. L.C. Sharma



THE ONLY INITIATIVE THAT COVERS ALL 17 SDG'S GOALS



## एबीपी न्यूज़ ब्रांड एक्सीलेंसी अवार्ड फॉर ऐजेंसी इन्नोवेशन ऑफ द ईपर पुरस्कार मुंबई में आईआईआरडी को मिला एक और सम्मान... इस वर्ष देश भर में गढ़े सफलता के झंडे

द रीव टाइम्स: हेम राज चौहान

वर्ष 2019 आईआईआरडी के लिए एक से बढ़कर एक उपलब्धि के साथ सफलता लिए हुए रहा है। इस वर्ष अनेक सामाजिक विकास, गतिविधियों और कार्यों में संस्था ने सफलता का परचम लहराया है। संस्था ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में अनुलोदी सहयोग दिया है जिसके लिए संस्था को देश भर में सराहना तो मिली ही, साथ ही अनेक बड़े और प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाज़ा गया है। इसी के चलते अब राष्ट्रीय समाचार ऐजेंसी ए बी पी द्वारा संस्था के नये एवं महत्वपूर्ण प्रभावी प्रयासों को सराहते हुए एबीपी न्यूज़ ब्रांड एक्सीलेंस अवार्ड फॉर ऐजेंसी इन्नोवेशन ऑफ द ईपर पुरस्कार से मुंबई में नवाज़ा गया है। संस्था के अनूठे प्रयास मिशन रीव जिसका वैश्विक प्रभाव देखा जा रहा है, के लिए संस्था को इसके लिए पुरस्कृत किया गया। गौरतलब है कि मिशन रीव द्वारा घर-घर की सेवाओं और मानवीय सामाजिक सरोकार में उत्तेजनीय योगदान के लिए विश्व भर में प्रशंसा प्राप्त की है तथा अपनी नायाब सेवाओं के माध्यम से देश भर में विभिन्न माध्यमों से प्रयासरत भी है। इसके लिए इसे 12 विभिन्न प्रभागों में विभाजित किया गया है जिसके अंतर्गत समस्त सेवाओं को प्रदान किया जाता है। समस्त कार्यप्रणाली और गतिविधियों को पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन



किया गया है। इसमें लोगों को उनकी समस्त समस्याओं और आवश्यकताओं को घर पर ही सेवाकर्मियों द्वारा प्रदान किया जाता है तथा इससे गांव-गांव में रोजगार के सैकड़ों अवसर भी प्राप्त हुए हैं और इसके भविष्य में भी और अधिक रोजगार प्राप्त होने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। मिशन रीव स्वास्थ्य, कृषि/बागवानी, शिक्षा और अन्य समस्त क्षेत्रों में बेहतरीन सेवाओं के साथ सरकार की सहयोगी की भूमिका में भी है। इसी के तहत द रीव टाइम्स समाचार पत्र को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है जिसमें सरकार की बेहतरीन योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को समाचार पत्र ने स्वैच्छिक रूप से प्रकाशित कर लोगों को गांव-गांव में जागरूक किया है।

संस्था को मुंबई के होटल ताज़ में एबीपी न्यूज़ ऐजेंसी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार को संस्था के प्रबंध निदेशक एवं मिशन रीव के प्रणेता एवं संस्थापक डॉ० एल सी शर्मा ने प्राप्त किया। उनके साथ संस्था की निदेशक सुषमा शर्मा एवं फ्लायर ग्रुप के सीईओ आनन्द नायर भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक डॉ० एल सी शर्मा ने कहा कि



पुरस्कार प्राप्त करने से कहीं अधिक इसकी गरिमा को बनाए रखने की चुनौती होती है जिसे संस्था और संस्था से जुड़े समस्त सेवाकर्मी अधिक प्रयासों और लगन से पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने इसके लिए देशभर में संस्था से जुड़े समस्त कर्मियों एवं मार्गदर्शकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

## रांची के 40 छात्रों ने समझी मिशन रीव की बारीकियाँ

द रीव टाइम्स ब्लूरो

रांची के जेवियर इंस्टीट्यूट रांची के करीब 40 छात्र एक्सपोजर विजिट पर आईआईआरडी कार्यालय शिमला पहुंचे। छात्रों की यह टीम संस्थान के डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रो. निर्जन साहु की अगुवाई में शिमला ब्रमण पर है। आईआईआरडी कार्यालय में छात्रों के लिए विशेष इंटरेक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया।

इस दौरान छात्रों ने बताया जेवियर इंस्टीट्यूट कैसे छात्रों के भविष्य संवारने में लगा है और कैसे यहां एक्सपोजर विजिट के माध्यम से उन्हें ग्रामीण विकास की



बारीकियों को समझ रहे हैं। इसके बाद आईआईआरडी की ओर से उन्हें मिशन रीव और आईआईआरडी की ओर से किए जा रहे विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इसके लिए मिशन रीव के विभिन्न प्रभागों पर प्रजेंटेशन देने के साथ ही सीएसआर प्रॉजेक्ट,

डीडीयूजीकेवाई और अन्य प्रोजेक्ट के बारे में भी छात्रों को जानकारी दी गई। इस दौरान छात्रों ने ग्रामीण विकास से जुड़े कई मुद्रदों और समस्याओं के बारे में चर्चा की और जाना कि मिशन रीव कैसे इन समस्याओं



का निवारण कर रहा है और गांवों में सुविधाएं प्रदान कर रहा है। छात्रों की ओर मिशन रीव कॉन्सेप्ट की काफी सराहना की गई।

## आसाम में विकास को गति दे सका आईआईआरडी

द रीव टाइम्स ब्लूरो

आईआईआरडी हिमाचल के साथ -साथ दूसरे प्रदेशों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, कर्नाटक समेत देश के दूसरे राज्यों में आईआईआरडी विकासात्मक गतिविधियों में अहम योगदान दे रहा है। बात युवाओं के कौशल विकास की हो, समार्ट एज्यूकेशन की हो या आधारभूत संरचना की, आईआईआरडी हर क्षेत्र में कई बड़े प्रोजेक्टों को अंजाम दे चुका है। पूर्वोत्तर राज्य आसाम इसका ताजा उदाहरण है।

आसाम को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए जहां इस आईआईआरडी गेल इंडिया के साथ मिलकर सीएसआर प्रोजेक्ट के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस शैक्षालयों का निर्माण करवाया जा रहा है वहां साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आरओ भी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों को आधुनिक तकनीक से शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्मार्ट क्लास रूम उपलब्ध कराने में संस्था ने सराहनीय कार्य किया है।

स्कूलों में आधुनिक शैक्षालयों का निर्माण - आईआईआरडी की ओर से सीएसआर प्रोजेक्ट के तहत आसाम के करीब 70 स्कूलों में स्वच्छ विद्यालय अभियान के मॉडल पर आधारित आधुनिक सुविधाओं से लैस शैक्षालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शैक्षालयों का निर्माण किया जा रहा है।



### स्मार्ट क्लास रूम

आसाम के 60 स्कूलों सीएसआर प्रोजेक्ट के तहत ही स्मार्ट क्लास रूम शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट क्लास रूम के तहत सभी तरह की तकनीकी

**स्कूलों में आर.ओ.** -आसाम के करीब 169 स्कूलों में आर.ओ. भी

लगाए जा रहे हैं ताकि स्कूल में पढ़ने

वाले बच्चों को साफ और स्वच्छ

जल मिल सके।

स्कूलों में बच्चों को

साफ पानी को लेकर अक्सर संशय बना रहता था। ऐसे

में जरूरी है कि स्कूलों में बच्चों को स्वच्छ जल की

आपूर्ति निश्चित की जाए। इस कड़ी में आसाम के

बरपेटा, नालबरी, कामरुल, कोकाराजार और चिरांग के

स्कूलों में आरओ लगाए जाएंगे।

**वाटर एटीएम-** सभी लोगों को पीने का साफ



पानी उपलब्ध कराने के लिए आईआईआरडी गेल इंडिया के साथ मिलकर आसाम में विभिन्न स्थानों पर वाटर एटीएम लगाने का कार्य भी कर रहा है। पहले चरण में इस प्रोजेक्ट के तहत उपायुक्त कार्यालय बरपेटा, एसडीसीएच पाठशाला, बरपेटा सीएचसी, सोरभोग सीएचसी, बरपेटा ताउन नियर एसबीआई ब्रांच, बजाली, सर्किंट हाऊस बरपेटा, एमसी कॉलेज बरपेटा, जीएलसी कॉलेज बरपेटा रोड, बारनगर कॉलेज सोरभोग, एसडीओ ऑफिस बजाली, बरपेटा रोड बस्टैंड में वाटर एटीएम लगाए जाने हैं।



# CSR in 2019-20

IIRD in association with GAIL India Limited is working towards holistic development, with primary focus on GAIL Pipeline Project-affected areas. GAIL has given mandate to IIRD for various Social/Rural Developmental works in the states of Assam, Madhya Pradesh, Bihar, West Bengal, Jharkhand, and Chandigarh. IIRD has joined hands with local stakeholders, Government Authorities, is working to implement the following programmes

for Classes 1 to 12. In the series, IIRD is going to install 40 Smart Classrooms in Jharkhand (Giridih and Khunti), and 40 in Karnataka (Dharwad). The initiative is going to directly benefit around 40,000 students.

In the line of Swachh Bharat Abhiyan, IIRD is installing 413 Waste Bins in Ujjain and Bhopal, MP, in coordination with the local Municipal Corporations. Recently, we also provided 7 tippers to Chandigarh

Wellness Centres. We are in the process of installing ROs in 330 schools of Jharkhand and 170 schools of Assam. Further, we have identified 12 Health and Wellness centres in Barpeta districts of Assam for installing water ATMs. These ROs and Water ATMs will directly and indirectly cater to the needs of around 1 lakh students and the general public.

In addition to this, we have designed clean and hygienic model of toilets for the schools in Assam. The Baseline Survey has been conducted in the identified locations and the schools have been finalised on the basis of the need assessment. 55 Schools have been shortlisted for the same, around 70 toilet blocks with 1 WC and 4 Urinals / trough for boys and 3 WCs for girls. We are constructing these toilets blocks with various facilities like wash basin, proper sanitation, covered drainage system, 24-hour water system, etc. At present, IIRD and GAIL are mutually working towards the overall development of schools in Assam, and thus, contributing towards the holistic development of the entire region.



Currently, IIRD is in the process of setting up 60 Smart Classrooms in various districts of Assam with World-Class Infrastructure i.e. 85' Interactive Board, Projector and all the required accessories. Further, we have provided the content for an effective e-learning

Municipal Corporation for Solid Waste Management. In Rural Regions, access to safe drinking water to the communities is a challenge and often poses safety risk due to the water-borne diseases. Therefore, to cater the needs among the communities, we are installing RO Plants and Water ATMs in Schools, Health and

## IIRD and CSR

Institute for Integrated Rural Development (IIRD) is a non-profit organization dedicated towards bringing rural prosperity through research and studies, training and capacity building, program implementation, technical support and consultancies and institutional networking in the national and global perspective.

Established in 2004, IIRD has the expertise in different fields and capacity to undertake ventures of Research and Analysis, Training & Capacity Building, Programme Planning and Implementation, Monitoring and Evaluation of the Developmental and Socio-Economic Projects. Approved & empanelled by various Departments, Ministries & PSUs for its quality standards, IIRD has been striving for innovations in all fields of its operations across the country and also internationally. Since its inception in 2004, IIRD has been instrumental in devising innovative strategies to expand its horizon and contributing in developing market place. IIRD envisages contributing meaningfully towards rapid, sustainable development of the people by gaining international quality standards and becoming a well-known, established and reliable destination for developmental solutions.

Since, last few years the IIRD is actively working on various CSR projects in various states under well-known PSU's like GAIL India Ltd, ONGC, SJVNL, EIL, NTPC etc. IIRD is working towards Environment Conservation and Sanitation through various CSR projects like providing tippers for solid management, providing and installing SS dustbins at public places, Construction of toilets for the welfare of students from Govt. Schools and general public, proving RO plants and Water ATM's etc. In addition

IIRD has also played an important role in the education through providing Smart Class Room Solution to the students of Govt Schools in various states. A huge number of students are benefited with this technological improvement.

India is the first country in the world to make corporate social responsibility (CSR) mandatory, following an amendment to the Companies Act, 2013 in April 2014. Businesses can invest their profits in areas such as education, poverty, gender equality, and hunger as part of any CSR compliance.

### CSR trends in India

Since the applicability of mandatory CSR provision in 2014, CSR spending by corporate India has increased significantly. In 2018, companies spent 47 percent higher as compared to the amount in 2014-15, contributing INR 7,536 crores to CSR initiatives, according

to a survey.

Listed companies in India spent INR 10,000 crore in various programs ranging from educational programs, skill development, social welfare, healthcare, and environment conservation, while the Prime Minister's Relief Fund saw an increase of 139 percent in CSR contribution over last one year.

The education sector received the maximum funding (38 percent of the total) followed by hunger, poverty, and healthcare (25 percent), environmental sustainability (12 percent), rural development (11 percent). Programs such as technology incubators, sports, armed forces, reducing inequalities saw negligible spends.

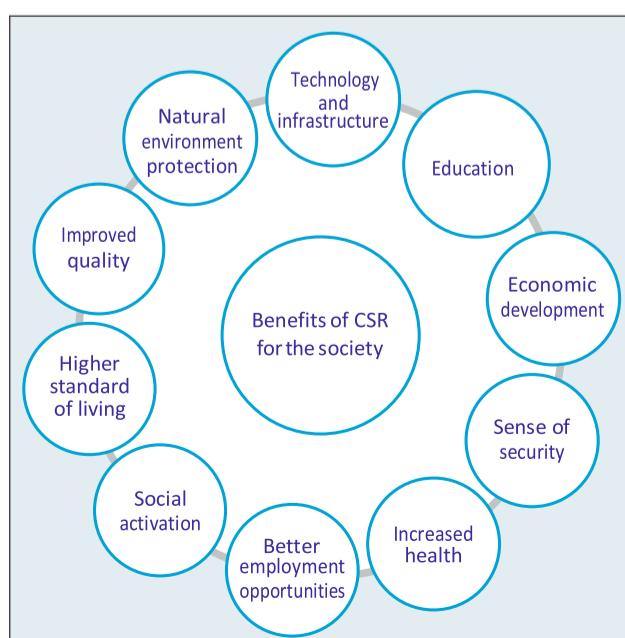
Taking into account the recent amendments to CSR provisions, industry research estimates CSR compliance to improve and range between 97 to 98 percent by FY 2019-20.

### CSR Benefits for the Organization

- Better brand recognition
- Positive business reputation
- Increased sales and customer loyalty
- Operational costs savings
- Better financial performance
- Greater ability to attract talent and retain staff
- Organizational growth

### CSR benefits for the Society

Apart from bringing a wide range of benefits for a



company, corporate social responsibility is supposed to, above all, contribute to the wellbeing of society. Delivering benefits to the whole of society should also be the prominent driver for business to start and continue CSR involvement (Perry and Towers, 2013). Although most researchers focus on the advantages of social responsibility to enterprises and why they should implement it, there are few that mention the gains of society.

Corporate involvement in local community's problems creates better ambiance in its surroundings. People who have been helped by company's activity are happier and benefit from a higher standard of living. Moreover, seeing that corporations care for communities' good makes everyone feels safer and significantly decreases corruption within society. Company's philanthropic activities generate benefits for the least advantaged, helping the needy and increasing trust. According to Arnold CSR also inspires fair competition.

Not only companies, but society as well benefits from better quality of products. Corporations' efforts to obey CSR rules make them eliminate all the defects at the production stage, resulting in diminishing the amount of complaints and increasing customer satisfaction. On the other hand, CSR changes in a company may lead to cost reduction, from which customers might also benefit, if it results in price fall.

Moreover, responsible behaviors of companies may inspire people in their surroundings to do the same. Thus, social activation enables them to experience emotional benefits from being involved in helping other people. It must be noted that company's success, which may be secured by implementing CSR, is also a success of local communities. A richer company can hire more employees on better conditions, providing substantial perks. As most of the workforce in the facility is usually drawn from surrounding areas, people from local communities are provided with better employment opportunities.

### Top 10 Companies with CSR Funds in INDIA

1. RELIANCE INDUSTRIES
2. TCS
3. ONGC
4. INDIAN OIL
5. HDFC BANK LTD
6. INFOSYS LTD
7. ITC LTD
8. COAL INDIA LTD
9. HDFC LTD
10. NTPS LTD

## तीन साल में 92 लाख रुपए होने के बाद भी अधूरा बलग स्कूल का भवन

द रीव टाइम्स

ठियोग उपमंडल के पांडवों से संबद्ध प्रसिद्ध प्राचीन गांव बलग में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का निर्माणाधीन भवन पैसे की कमी के कारण अवूरा पड़ा है। इस स्कूल का यह भवन 2010 से प्रस्तावित था। उस समय इस



भवन को बनाने का एस्टीमेट एक करोड़ 13 लाख था लेकिन पैसा नहीं होने के कारण

इसका कार्य 6 साल बाद जुलाई 2016 में लोकनिर्माण विभाग ने शुरू किया।

अब इसकी लागत दोगुनी से भी अधिक हो चुकी है। भवन के लिए नियमित रूप से पैसा न मिलने के कारण तीन सालों में इस भवन की दो मंजिले ही बन पाई है।

## शिमला के सुन्नी में 2.96 करोड़ रुपए से बनेगी महाशीर हैचरी

द रीव टाइम्स

दुनिया की सबसे कठिन मछली माने जाने वाली स्वर्ण महाशीर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शिमला के सुन्नी में 2.96 करोड़ की लागत से नई महाशीर हैचरी का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसका एक प्रोजेक्ट तैयार किया राज्य सरकार यहां पर



इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्प

प्रजनन इकाई स्थापित करेगी ताकि सरकार विलुप्त होती इस मछली का संरक्षण कर सके और लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सुनित कर सके। स्वर्ण महाशीर की पैदावार को बढ़ावा देने के सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में 10893 परिवार को लाभ होगा। प्रदेश में गोल्डन माहशीर के उत्पादन में हर साल बढ़ोतारी की जा रही है।

## अधूरा न्याय पूरा करें सरकार : गुड़िया न्याय मंच

द रीव टाइम्स

गुड़िया न्याय मंच ने 4 जुलाई 2017 को तांदी जंगल में हुई गुड़िया की हत्या व बलात्कार के मामले में सीबीआई कोर्ट चंडीगढ़ में फोरेंसिक विभाग के दो सहायक निदेशकों के बयानों का संज्ञान लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुड़िया मामले की पुनः जांच की मांग की है। मंच ने प्रदेश सरकार को आगाह किया है कि वह गुड़िया को न्याय देने के लिए तुरन्त उचित कदम उठाए अन्यथा गुड़िया न्याय मंच दोबारा से इस मुद्दे पर सङ्केतों पर उत्तर आएगा।

गुड़िया न्याय मंच के सह संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फोरेंसिक विभाग के दो



सहायक निदेशकों के बयान के बाद अब गुड़िया मामले में दूध का दूध व पानी का पानी करने के लिए व पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाने के लिए दोबारा से इस मामले की जांच करनी चाहिए। गैरतलब है कि भाजपा ने चुनाव के वक्त गुड़िया मामले को प्रमुख मुद्दा बनाया था अतः अब वक्त आ गया है कि वह अपने

वायदे को पूर्ण करें व इस मामले की तह तक जाने के लिए न्यायिक जांच गठित करें। प्रदेश सरकार को तुरन्त इस जांच को शुरू करना चाहिए। सीबीआई अपनी जांच पूर्ण कर चुकी है अतः प्रदेश सरकार को अलग से निष्पक्ष जांच करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीबीआई कोर्ट में चल रही कार्रवाई से एक के बाद एक कड़ियाँ खुल रही हैं। गुड़िया न्याय मंच शुरू से इस बात को कहता रहा है कि गुड़िया का बलात्कार व निर्मम हत्या किसी एक दरिद्रे का कार्य नहीं था बल्कि यह एक सामूहिक सुनियोजित जघन्य अपराध था। इस अपराध में शामिल असली अपराधियों को राजनेताओं, नौकरशाहों व प्रधावशाली व्यक्तियों का आश्रय रहा।

## नशे से कहीं अधिक मुल्यवान है जीवन : संस्था

द रीव टाइम्स ब्लूरो

ब्लैक ब्लैकेट वेलफारे सोसाइटी (ठसंबा ठसंदामजैं मसतिम म्कनबंजपवै वैबपमजल) संस्था की सचिव मीनाक्षी रघुवंशी ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन द्वारा मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान में संस्था अपना सहयोग दे रही है व विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यकर्मों का आयोजन किया जा रहा है।

संस्था द्वारा शिमला शहर के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में युवाओं से सीधा संवाद साधा गया है व उन्हें नशे से उनके शरीर व जीवन के हर पहलू में होने वाले नकारात्मक परिणामों से अवगत करवाया जा रहा है। संस्था के अनुभवी काउन्सलर व योग के



अनुभवी ट्रेनरों द्वारा युवाओं में अपने मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी बदलाव करने पर बल दिया जा रहा है व सरल टेक्निक के माध्यम से कैसे युवा खुद को नशे से बचा कर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक ढंग से प्रयोग करे इस बात का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रघुवंशी ने बताया की अब तक संस्था द्वारा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अनुभवी द्वारा युवाओं से अवगत करवाने के लिए भी प्रेरित करते हैं।

अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं को नशे से दूर रहने हेतु जरूरी जानकारी दी गई है व इसके साथ साथ पंचायत के प्रतिनिधियों व सदस्यों को भी जागरूक करने का कार्यक्रम है। संस्था के अध्यक्ष पुनीत कुमार, योग ट्रेनर उमेश हरनोट व काउन्सलर दीपक शर्मा बेहद सरल शब्दों में युवाओं से संवाद साथ उन्हें नशे से दूर रहने के न केवल टिप्प देते हैं साथ ही साथ उन्हें करियर से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध करवा रहे हैं। संस्था के सदस्य युवाओं को आजीवन किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक या आर्थिक परेशानी आने पर भी किसी तरह का व्यसन न करने का प्रण करवा रहे हैं व साथ साथ अपने साथी अपने दोस्तों को भी नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाने के लिए भी प्रेरित करते हैं।

## पुलिस करें ठोस कार्यवाही – नागरिक सभा

द रीव टाइम्स ब्लूरो

है व इसमें हत्या का पूरा शक जताया है। प्रतिनिधिमंडल में नागरिक सभा अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, उपाध्यक्ष बलबीर पराशर, सचिव सोनिया सबरबाल, मृतक नरेश कुमार के पिता सुनील कुमार, माता सरोज देवी, चाचा अनिल कुमार, डोला राम, रजनी देवी, राजेन्द्र, निशा, अनु, रोमा, रुपा, गीता, छुआरा, बलविंद्र, बाल व छोटू आदि शामिल हैं। नागरिक सभा अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि नरेश कुमार सपुत्र श्री सुनील कुमार दो अक्टूबर 2019 को रामलीला देखने के बाद दूर से अचानक गायब हो गया था। इस सन्दर्भ में घर वालों की ओर से थाना बालुगंज के अंतर्गत जतोग जांच अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई अमल में लाएं। नागरिक सभा ने इसे आत्महत्या मानने से साफ इंकार किया

है। नरेश कुमार का मोबाइल नंबर कई दिन तक कार्य करता रहा। इस दौरान उसके मोबाइल की लोकेशन चिंतपूर्णी, जीरकपुर व चंडीगढ़ आदि में भी पाई गई। इस दौरान घरवालों से उसकी बातचीत भी हुई। उसने किसी के मोबाइल से घर वालों से बातचीत भी की। नरेश कुमार का शव 20 नवम्बर को जब बरामद हुआ तो उसके बाद मीडिया की न्यूज व पुलिस के बयानों से यह भ्रम पैदा हुआ है कि दोनों यह मानकर ही चल रहे हैं कि यह एक आत्महत्या है क्योंकि शव पेड़ से लटका हुआ मिला।

## सरकार कानून बनाए : विजेन्द्र मेहरा

द रीव टाइम्स ब्लूरो

जाए। मंच ने मांग की है कि निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया व फीसों के संचालन के लिए प्रदेश सरकार आगामी धर्मशाला विधान सभा सत्र में कानून लेकर आए व एक रेगुलेटरी कमीशन का गठन करें। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि प्रदेश में कार्यरत लगभग 2700 निजी स्कूल नियमों की सरेआम धर्मशाला तक रहे हैं तथा

हिमाचल प्रदेश निजी स्कूल संचालन अधिनियम 1997, नियम 2003, सीबीएसई गाइडलाइन्स 2005, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अधिसूचना 2014, शिक्षा का अधिकार कानून 2009, हिमाचल उच्च न्यायालय के 2016 के दिशानिर्देशों व वर्ष 2018 के उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन्ज नियमों की सरेआम धर्मशाला से लागू किया

## शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति

16-31 दिसम्बर, 2019 03

## महंगाई के खिलाफ लाम्बांद हुई सीपीआईएम

द रीव टाइम्स ब्लूरो

सीपीआईएम राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश के आत्मान पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ पूरे प्रदेश में जिला व ब्लाहक मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन किए गए। इसके तहत शिमला के डीसी अहफिस पर पार्टी द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया जिसमें लगभग चार सौ लोगों ने भाग लिया। इसके बाद डीसी अहफिस से लोअर बाजार होते हुए शेर-ए-पंजाब तक रैली का आयोजन किया गया। नाज पर जनसभा का आयोजन किया गया। प्रदर्शन में पार्टी नेता संजय चौहान, डॉ कुलदीप तनवर, विजेंद्र मेहरा, जगत राम, फालमा चौहान, बलबीर पराशर, आदि मौजूद रहे।



## विदेशी परिदंडों से गुलजार हुई श्री रेणुका झील

द रीव टाइम्स ब्लूरो, सिरमौर

प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री रेणुका जी इन दिनों विदेशी परिदंडों से गुलजार है। ठंडक का अहसास होते ही सिरमौर में साइबरियन पक्षियों के ने डेरा जमा लिया है। पक्षियों की चहचहाहट से झील का सौंदर्य भी निखर उठा है। झील के अंतिम छोर पर सैकड़ों विदेशी परिदंडे डेरा जमाए हैं। वन्य प्राणी विभाग के अनुसार इन दिनों सात प्रजातियों के करीब 253 परिदंडे पहुंच चुके हैं। इनकी संख्या में अभी और इजाफा होने की उम्मीद है। मौसम में आए बदलाव के बाद श्री रेणुका जी में प्रवासी परिदंडों की चहचहाहट गूंजनी शुरू हो गई है। पिछले वर्ष भी यहां पक्षियों की दस प्रजातियों ने डेरा डाला था।

इस वर्ष शुरुआती दौर में अभी सात प्रजातियों के 253 परिदंडों ने रेणुका में दस्तक दे दी है। हालांकि, हर वर्ष यह पक्षी दिसंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान ही रेणुका में दिखाई देते थे, लेकिन इस वर्ष एक माह पूर्व



ही यह पक्षी रेणुका पहुंच चुके हैं। वन्य प्राणी विभाग ने इन मेहमान परिदंडों की अवधारणा के लिए पुख्ता प्रबंध कर रखे हैं। रेणुका झील के अंतिम छोर पर इन पक्षियों की जलक्रीड़ाएं और चहचहाहट दिखाई देने लगी हैं। विभाग के अनुसार अभी तक रेणुका पहुंचे इन पक्षियों में यूरोशियन मोहरण 200, कॉमन कृट 18, मेलाड 20, रेड कस्टर पोचर्ड 4, यूरोशियन टीट 6, नॉर्दन साउलर 1, ग्रेट कॉमरेंट 4 सामिल हैं। जिन पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नजर रखी जा रही है। ये पक्षी हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय कर यहां पहुंचते हैं। करीब तीन माह का समय यहां ब्यतीत करने के बाद फरवरी के शुरू में ये परिदंड स्वदेश लौट जाएंगे।

## रसोई से प्याज गायब जीरे का लग रहा तड़का, लोगों में आक्रोश

  
द रीव टाइम्स ब्लूरो, सिरमौर  
प्याज की कीमत में आए उछाल से रसोईधरों का बजट बिगड़ गया है। सौ रुपये के पार कीमत पहुंचने से लोग अब बिना प्याज के दाल-सब्जी बनाने के लिए विवश हो गए हैं। रसोई से प्याज का तड़का गायब हो गया है। लहसुन, अदरक और जीरा से काम चलाया जा रहा है। सरकार ने लोगों को राहत प्रदान

करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। जिससे लोगों में आक्रोश है। किसानों से प्यास सस्ते दामों पर खरीदा गया, जबकि अब कीमत सातवें आसमान पर पहुंच गई है। कीमतों में आए उछाल से कई लोगों में केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा भी फूट रहा है। लोग इसके लिए सीधा केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर भी लोग जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल में भी सस्ती दर पर प्याज मुहैया करवाने की मांग उठने लगी है। प्याज की बढ़ी कीमतों पर अमर उजाला ने लोगों की राय जानी। गृहिणी, कारोबारी और किसानों ने इस मामले पर जहां अपनी व्यथा सुनाई वहीं सरकार की नीतियों को भी दोषी ठहराया।

## फिर चलेगा कछा धारियों पर डंडा, धारा 144 लागू

द रीव टाइम्स ब्लूरो, सिरमौर

नगर परिषद की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ फिर अभियान छेड़ने जा रही है। पांच दिसंबर से नगर परिषद अभियान चलाएगी। उच्च न्यायालय के आदेश पर अवैध कब्जे हटाने के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने नगर परिषद नाहन के दायरे में धारा 144 लागू कर दी है।

इसके तहत शहर में रह रहे लोगों को अपने लाइसेंसी हथियार पुलिस थाना में जमा करवाने होंगे। अवैध कब्जे हटाने के लिए नगर परिषद ने स्पेशल टारक फोर्स का गठन भी किया है। नगर परिषद की ओर से संदिग्ध माने गए 88 मामलों की निशानदेही के बाद 68 कब्जों को हटाया जाना था। इसके लिए कब्जाधारियों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इससे पहले चले दो अभियानों के दौरान नगर परिषद ने अधिकतर कब्जे हटाते हुए हैं। लेकिन, कुछ लोगों ने स्वयं कब्जे तोड़ने शुरू किए थे, जिन्हें नगर परिषद ने नहीं छेड़ा। लोगों ने स्वयं कब्जे पूरी तरह से हटाए या नहीं? नगर परिषद की ओर से



चिह्नित पूरे क्षेत्र से कब्जा हटा या नहीं? इसकी मौके पर जाकर तस्वीक की जाएगी। जिन्होंने कब्जे पूरे नहीं हटाए हैं, उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। उधर, कब्जे हटाने के लिए प्रशासन ने भी कड़े प्रबंध कर लिए हैं। पुलिस सुरक्षा के बीच अवैध कब्जे हटाने की मुहिम चलाई जाएगी। मंगलवार देर शाम उपायुक्त ने बतौर जिला दंडाधिकारी अधिसूचना जारी करते हुए नाहन नगर परिषद क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है। अतिरिक्त उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कहा कि आदेशों के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र के दायरे में आने वाले सभी लोगों को अपने लाइसेंसी हथियार पुलिस थाने में जमा करवाने होंगे। सभी को चार दिसंबर शाम पांच बजे तक हथियार जमा करवाने के लिए कहा गया है।

## ददाहू अस्पताल में 20 फीसदी तक बढ़ा दिए यूजर चार्जिंज

द रीव टाइम्स ब्लूरो, सिरमौर

सिविल अस्पताल ददाहू में रोगियों को दी की जाने वाली तमाम सुविधाओं की दरों में भी 15-20 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी की गई है। मेडिकल बनवाने के शुल्क में भी इजाफा किया गया है। अब मेडिकल बनवाने पर 250 रुपये देने होंगे। पहले यह राशि 200 रुपये थी। जबकि, बंदूक लाइसेंस के मेडिकल के लिए यह राशि 500 रुपये निर्धारित की गई है। यह निर्णय मंगलवार को हुई रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) की बैठक में लिए गए। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम नाहन विवेक शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल ददाहू में आने वाले रोगियों को हरसंभव बुनियादी सुविधा प्रदान करने के विशेष प्रयास किए जाएंगे। अस्पताल की आय

में इजाफा करने के लिए संसाधन जुटाए जाएंगे। सिविल अस्पताल ददाहू में प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को अब अपनी जेब ढीली करनी होगी। अस्पताल से फर्स्ट एड का प्रशिक्षण लेने पर ऐसे प्रशिक्षितों को पांच सौ रुपये शुल्क अदा करना पड़ेगा। बैठक में अस्पताल में वाहन पारिकर्ता के ठेके पर देने, अस्पताल परिसर में कैटीन खोलने, सहकारी दवा की एक दुकान खोलने का फैसला भी लिया गया। अस्पताल में कुछ आवश्यक सुविधाओं को जुटाने और मरम्मत आदि के कार्यों पर भी करीब छह लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इससे आरकेएस के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों के वेतन का नियमित भुगतान किया जाएगा।

## सोलन, सिरमौर, ऊना

### सरकारी जमीन को अपना बता, हड्डप लिए 40 हजार रुपये

द रीव टाइम्स ब्लूरो, ऊना

मैहतपुर के साथ लगते बनगढ़ गांव की महिला को जमीन पर नाजायज कब्जा किए जाने की पड़ोसियों की शिकायत का दाव उल्टा पड़ गया है।

एसपी तथा जिप सदस्य पंकज सहोड़ को दी गई लिंगित शिकायत के आधार पर जब मीडिया ने मामले को उठाया तो राजस्व विभाग के कान खड़े हो गए। पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर विभागीय अधिकारियों

के लिए विदेशी व्यापक धोखे से उसकी जमीन हड्डपने के संगीन आरोप लगाते हुए एसपी ऊना को तथा क्षेत्र के जिप सदस्य पंकज सहोड़ को लिंगित शिकायत दी थी।

बुधवार को जिला परिषद सदस्य पंकज सहोड़, स्थानीय पंचायत प्रधान प्रोमिला देवी, उपप्रधान पंकज कुमार, कानूनगो इकबाल सिंह, पटवारी अमरीक सिंह, पंचायत सदस्य नंद किशोर सतपाल शर्मा, प्रमोद सिंह, जगपाल सिंह, सुनीता, पूजा, शकुनता, राज कुमार तथा मोहन लाल की मौजूदी में उत्तम मामले की पड़ताल की गई।

जमीन की पैमाइश के बाद पाया गया कि जिस जमीन को अपना बता कर राजस्वारी ने पेयजल की तरह से लेकर विभागीय अधिकारियों से लेकर विभाग के अधिकारी ने राजस्वारी को उत्तम मामले की पड़ताल की गई।

जमीन की पैमाइश के बाद पाया गया कि



विभागीय अधिकारी ने राजस्वारी को उत्तम मामले की पड़ताल की गई। एसपी दिवाकर शर्मा ने कहा कि अगर उत्तम महिला के पड़ोसियों की उन्हें शिकायत मिलती है, तो अवश्य उत्तम महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

### मुख्य विकास अधिकारी को बायो वेर्स्ट के योजनाबद्ध निपटारे के निर्दश

वैज्ञानिक निपटान पर ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सभी संबंधित अधिकारियों को कार्य योजना बनाकर काम करना होगा।

बैठक में आए अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में ठोस और तरल कूड़ा-कचरा प्रबंधन को लेकर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लोगों में व्यापक जन जागरूकता लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर कार्य कर रहा है।

सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना इस दिशा में व्यवहारिक कदम है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के संबंध में समाज को जागर

## तकनीकी विवि भूमि सौदे और लैंड चेंज मामले की दोबारा जांच शुरू

द रीव टाइम्स ब्लूरो, हमीरपुर

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर को आवंटित जमीन को गलत तरीके से कारोबारियों के नाम करने के मामले की पैने दो वर्ष बाद दोबारा जांच शुरू हो गई है। लेकिन जिन पटवारी और कानूनगों को निशानदेही के लिए रिकॉर्ड देने का काम सौंपा था, वे ऐन मौके पर छुट्टी चले गए। दूसरे पटवारी की ड्यूटी लगाई गई लेकिन बिना

## लंबलू को सवा दो साल बाद फिर उप-तहसील बनाने की घोषणा

द रीव टाइम्स ब्लूरो, हमीरपुर

विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर के अंतर्गत लंबलू में सवा दो साल के बाद फिर से सब तहसील की घोषणा हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दहोनी स्थित प्रदेश तकनीकी विवि परिसर में आवोजित जनसभा में सदर विधायक की मांग पर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें ज्ञात हुआ है कि उपतहसील की घोषणा वीरभद्र सरकार ने जाते-जाते की थी। लेकिन, वर्तमान सरकार अपने इसी

कानूनगों निशानदेही नहीं हुई। फिर दूसरी टीम को भेजकर से निशानदेही का काम किया गया है।

तकनीकी विवि करोड़ों रुपये की इस जमीन को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। विवि ने एसडीएम हमीरपुर से इस मामले में सदर के बजाय किसी दूसरे तहसीलदार से जांच करवाने की अपील की है। एसडीएम ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए टौणी



देवी तहसीलदार को जांच और निशानदेही के आदेश दिए हैं।

कार्यकाल में इस उपतहसील को शुरू भी करेगी। 4 सितंबर 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पूर्व विधायक कुलरीप पठानिया के अनुरोध पर लंबलू में उपतहसील की घोषणा की थी। लेकिन, दो साल के बाद भी यह शुरू नहीं हुई।

अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणा और आश्वासन के बाद लोगों में फिर से उम्मीद जगी है। लेकिन, उपतहसील को खोलने से पूर्व कैबिनेट की बैठक में इस

घोषणा पर मुहर लगाने और नायब तहसीलदार, कानूनगों व पटवारी समेत अन्य स्टाफ के पद सुनित करने की आवश्यकता रहेगी। जिस पर न केवल हमीरपुर की जनता बल्कि विपक्ष की भी नजर रहेगी। जयराम ने कहा कि लंबलू में पेयजल योजना का भले ही पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सरकार ने शिलान्यास किया था, लेकिन बजट की कोई व्यवस्था नहीं की। वर्तमान सरकार ने इस पेयजल स्कीम के लिए बजट स्वीकृत किया है।



पड़ती थी। जिससे उनका आधे से ज्यादा दिन पर्ची बनवाने में ही चला जाता था, जबकि शेष समय में ओपीडी के बाहर भीड़ होने के चलते कई बार उन्हें समय पर जांच से वंचित रहना पड़ता था।

## मेडिकल कॉलेज में अब गर्भवतियों की अलग बनेंगी पर्ची

द रीव टाइम्स ब्लूरो, हमीरपुर

डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में गर्भवतियों की ओपीडी पर्ची अब अलग से बनेगी। अस्पताल प्रबंधन ने गर्भवतियों की सुविधा के लिए अलग से पर्ची काउंटर बनाया है। पूर्व में अस्पताल में महज तीन ही पर्ची काउंटर थे। इनमें से एक महिलाओं, एक पुरुषों और एक अलग से सीनियर सिटीजन के लिए था। अब अस्पताल में चार पर्ची काउंटर बनाए गए हैं। चौथा काउंटर गर्भवतियों के लिए है। इससे

पूर्व अस्पताल आने वाली गर्भवती महिलाएं काउंटर की कतार में खड़ी होकर पर्चियां बनवाने को मजबूर थी। ऐसे में रोजाना महिलाओं के काउंटर पर भीड़ रहने के चलते गर्भवतियों को परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब इन्हें राहत मिलेगी। वर्तमान में गयनी ओपीडी में रोजाना 300 से अधिक महिलाएं आती हैं। इनमें से करीब डेढ़ सौ महिलाएं गर्भवती होती हैं, जो अपनी जांच को आती हैं। गर्भवतियों को आम महिलाओं की तरह ही लंबी कतार में खड़ी होकर पर्ची बनवाना

## स्वास्थ्य केंद्र हटवाड़ के मरम्मत कार्यों के लिए पास हुए 4 लाख

द रीव टाइम्स ब्लूरो, बिलासपुर

स्वास्थ्य खंड धुमारवां के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हटवाड़ में रोगी कल्याण समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष उपमंडलाधिकारी धुमारवां शशी पाल शर्मा की अध्यक्षता में की गई। इसमें खंड चिकित्सा अधिकारी धुमारवां डॉ. अभिनीत शर्मा भी उपस्थित रहे।

बैठक में रोगी कल्याण समिति के सचिव डॉ.

खर्च किया गया। डॉ. भारद्वाज ने बताया कि अब समिति के पास 2,72,619 रुपये हैं। समिति के अध्यक्ष उपमंडलाधिकारी धुमारवां शशी पाल शर्मा ने बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हटवाड़ के लिए रोगी कल्याण समिति में वर्ष 2019–2020 में छोटी-मोटी मरम्मत और कार्यों के लिए 4,04,210 रुपये खर्च करने का प्रस्ताव पास किया गया।

## पौंग झील किनारे बसे देहरा और दूसरे गांवों की जमीन धंस रही

द रीव टाइम्स ब्लूरो, कांगड़ा

ब्यास टट पर बसे नगर परिषद देहरा और बनेड़ खड़ के किनारे बसे बंगोली गांव की ओर धीरे-धीरे एक खतरा बढ़ रहा है। ब्यास नदी के किनारे बसे होने के कारण देहरा शहर और बनेड़ खड़ के तेज बहाव के कारण बंगोली गांव की जमीन धारे-धीरे धंस रही है। यही नहीं ब्यास नदी किनारे बसे दूसरे गांवों में भी यह स्थिति देखने को मिल रही है। इससे लोग दहशत में हैं।

एनआईटी हमीरपुर की एक टेक्निकल टीम

शीघ्र ही पौंग झील किनारे पर बसे देहरा

शहर और उसके साथ लगते गांवों का दौरा करेगी। इसके अलावा जिला प्रशासन

बीबीएमबी को भी नोटिस जारी करेगा। एनआईटी हमीरपुर की टेक्निकल टीम देहरा शहर और बंगोली गांव सहित दूसरे इलाके के गांवों का दौरा कर सर्वे रिपोर्ट तैयार कर सरकार और जिला प्रशासन को सौंपेगी कि इन इलाकों की जमीन धीरे-धीरे वर्षों धंस रही है। हाल ही में जिलाधीश कांगड़ा राकेश प्रजापति ने देहरा के विधायक होशियार सिंह के आग्रह पर देहरा शहर और ब्यास नदी किनारे दूसरे गांवों को दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने भी पाया था कि पौंग झील किनारे बसे कुछ इलाकों की जमीन धीरे-धीरे धंस रही है।

निर्धारण कर पक्की बूर्जियां लगा दी गई हैं।

निशानदेही के इस मौके पर राजस्व विभाग

हमीरपुर और बिलासपुर के कानूनगों व पटवारियों में कानूनगों बिलासपुर धर्मसिंह,

कानूनगों हमीरपुर सुरेश, पटवारी पंजक

में जमीन धंस रही है। असली स्वरूप को लगातार हो रहे खनन से खो चुकी है। खड़ पहले के मुताबिक 10 से 15 फुट नीचे जा चुकी है जिस कारण पेयजल व सिंचाई योजनाओं पर खासा असर पड़ रहा है। इसके अलावा स्कूलों के किनारे में इन वर्करों को साफ-सफाई रखने की हिदायत भी दी गई है।

## मॉरीशस के पीएम ने पत्नी के साथ बगलामुखी मंदिर में करवाया अनुष्ठान

द रीव टाइम्स ब्लूरो, कांगड़ा

मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगानाथ ने हाल ही में पत्नी के साथ बगलामुखी मां के दर्शन किए और हवन-यज्ञ करवाया। वे मंदिर में करीब दो घंटे तक रुके। महंत जगत गिरी ने उन्हें माता बगलामुखी की फोटो और चुनरी भेंट की। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर छावनी में तबदील कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि दो माह पहले मॉरीशस के प्रधानमंत्री 12 नवंबर को एक बार फिर पीएम पद की शपथ की पत्नी बगलामुखी मंदिर में पहुंची थीं और

हिमाचल की प्रसिद्ध इस झील में पहुंचे 61 हजार विदेशी परिदेशी

द रीव टाइम्स ब्लूरो, कांगड़ा

विश्व प्रसिद्ध रामसर साइट वेटलैंड महाराणा प्रताप सागर (पौंग झील) में ठंड बढ़ने के साथ ही प्रवासी पक्षियों का आगमन बढ़ना शुरू हो गया है। अभी तक की हुई सामान्य

## मुख्यमंत्री ने दी हमीरपुर को 133 करोड़ रुपये की सौगात

द रीव टाइम्स ब्लूरो, हमीरपुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में अपने हमीरपुर दौरे के दौरान जिलावासियों को 133.91 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। पेयजल स्कीम, बिजली उपक्रम समेत करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाले भवनों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। उन्होंने तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। यह भवन 66.61 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। उन्होंने एक टैक ऐप, शोध पत्रिका और ई-लाइब्रेरी का विमोचन भी किया। उन्होंने तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर को 10 करोड़ रुपये का आवर्ती अनुदान प्रदान करने की घोषणा भी की।

## भुंतर के तेगूबेहड़ में 50 विस्तरों के नागरिक अस्पताल का शुभारंभ



द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

जिला कुल्लू के भुंतर के पास तेगूबेहड़ में नागरिक अस्पताल का शुभारंभ हो गया वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने तेगूबेहड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भुंतर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेगूबेहड़ के विलय के पश्चात इस 50 विस्तर वाले नागरिक अस्पताल को

## वैकसीनेशन के साथ लावारिस कुर्तों के लिए बनाया शेल्टर

द रीव टाइम्स, कुल्लू

माझनस तापमान के बीच पशुपालन विभाग ने सेव डॉग्स नाम से अभियान छेड़ा है। इस अभियान के तहत बर्फबारी के बीच लाहौल घाटी में धूम रहे लावारिस कुर्तों को सुरक्षित आवास की सुविधा मुहूर्हा करवाई जा रही है। धून्य से 10 डिग्री नीचे तापमान के बीच इन कुर्तों को न तो खाने कुछ मिल रहा और न ही सिर छुपाने के लिए जगह। यही वजह है कि लाहौल घाटी के कई हिस्सों में अब तक भूख और ठंडे से कई कुर्तों और बिल्लियों की जान जा चुकी है। ठंडे में हालात ऐसे हैं कि

## तुंग पंचायत न सड़क सुविधा, न स्वास्थ्य सेवाएं मिल रहीं



द रीव टाइम्स ब्यूरो कुल्लू

तीर्थन घाटी की ग्राम पंचायत तुंग के कई गांवों में मरीज सड़क के अभाव में आधे रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। पंचायत के गांव मनाणी, धारा, शलिंगा, चिपाणी, नाइणी, नगड़ार, मलैथर सड़क सुविधा से वंचित हैं। आलम यह है कि यहां के बासिन्दों को सड़क तक पहुंचने के लिए कई किमी पैदल चलना

## छोटी काशी मंडी को भव्य बनाने के लिए बनेंगे चार प्रवेशद्वार : जयराम

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला मंडी में कार्यान्वित की जा रही विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि छोटी काशी मंडी को अधिक सुंदर बनाने के लिए चार प्रवेश बिंदुओं पर प्रवेशद्वार बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने मंडी शहर में भीड़-भाड़ कम करने के लिए अधिकारियों को बाईपास निर्माण की संभावनाएं खोजने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को व्यास नदी के दोनों किनारों पर पैदल रास्ते के निर्माण की संभावनाओं का पता लगाने का भी सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगनीधार में

## स्कूल के बच्चों को जल्द मिलेगी बैग की सौगात

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

जिला चंबा के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जल्द ही स्कूल बैग की सौगात मिलेगी। विभिन्न शिक्षा खंडों के लिए पहुंची सप्लाई में एक सैंपल (रेंडमली) सेलेक्ट किया गया है। विभाग ने इसे जांच के लिए शिमला की प्रयोगशाला भेज दिया है। विभाग के मुताबिक जैसे ही सैंपल पास होगा। इसके बाद सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्कूल बैग का आवंटन शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार सरकार की ओर सरकारी स्कूलों

## हैदराबाद कांड़: धरने पर बैठीं देश की सबसे युवा प्रधान जबना

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

हैदराबाद में हैवानियत की घटना और देश में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ देश की सबसे युवा प्रधान एवं ओरिएंटल फाउंडेशन की संस्थापक जबना चौहान को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठी। जबना के साथ कई राज्यों से आए संगठनों व संस्थाओं के पदाधिकारी भी धरने में शामिल हुए। हिमाचल की मंडी की जबना चौहान ने

जनता की सुविधा के लिए समर्पित किया। इस दौरान गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को तेजी से सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि लोगों को सस्ती और सुलभ उपचार सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के स्तरोन्त होने से क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पर भी दबाव कम होगा। यहां 24 घंटे लोगों को उपचार सुविधाएं प्रदान होंगी। मणिकर्ण घाटी, भुंतर जैसा बड़ा क्षेत्र इस अस्पताल पर निर्भर करेगा। अस्पताल में पूर्व में 22 पद स्वीकृत थे, अब बढ़कर इनकी संख्या 41 कर दी गई है। प्रसव रूम में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी,

अस्पताल के पास शेल्टर बनाया गया है। ठंडे से पांच पिल्ले और एक बिल्ली मृत मिले हैं। जांच के दौरान पता चला है कि इनकी मौत अत्यधिक ठंड और भूख से हुई है। विभाग ने इस तरह के लावारिस कुर्तों की जानकारी तत्काल देने की अपील की है।

प्रकाश ने कहा कि पांच दशक पहले पंचायत के चार गांवों को सड़क से जोड़ा गया। लेकिन इसके बाद सरकार व प्रशासन ने अन्य गांवों को सड़क सुविधा प्रदान करने की जरूरत नहीं मिल पाई है। पंचायत में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए महज उप स्वास्थ्य केंद्र बढ़ाहड़ है। यहां पर डॉक्टर न मिलने से लोगों को मुश्किलें आती हैं। बर्फबारी के दिनों में बिजली गुल होने पर ग्रामीणों की अंधेरे में ही रातें कटती हैं। दूरसंचार सेवाएं भी ठप हो जाती हैं। भारी बर्फबारी के बाद जब गांवों में बिजली बाधित हो जाती है तो कई दिनों तक आपूर्ति बहाल नहीं होती है। ग्रामीण लोत राम, पृथी चंद, लज्जे राम, राम सिंह, भवन बाधित रहती है।

शिवार्थित समय पर पूरा किए जाए। ताकि परियोजनाओं की लागत में वृद्धि न हो और लोगों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के संतुलित एवं समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

यह आपूर्ति सीधा खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों का वार्षिकों को गई है। सैंपल की रिपोर्ट के बाद यह सौगात बच्चों को मिलेगी। गौरतलब है कि एक तरफ जहां सरकारी स्कूली बच्चों को निशुल्क वर्दियां दी रही हैं तो वहीं, अब स्कूल बैग देने का प्रावधान किया है। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक चंबा फौजा सिंह ने बताया कि स्कूल बैग की जांच के लिए सैंपल ब्लॉक स्तर पर भेजें गए हैं। जैसे ही सैंपल अप्रूव होंगे, इसके बाद आवंटन शुरू कर दिया जाएगा। छोटी काशी मंडी की शान कहे जाने वाले 142 साल पुराने विकटोरिया पुल के

## गिले में गोसदन बने न गो सेवा आयोग का गढ़न

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

जिला कुल्लू की सड़कों पर धूम रहे लावारिस पशु सरकार के गो संरक्षण के दावों की पोल खोल रहे हैं। लावारिस मवेशियों को राहत देने के लिए सरकार सिर्फ गोसदन निर्माण की कोरी घोषणा करती है। घोषणा के बाद काम हुआ या नहीं इस पर फिर कोई ध्यान नहीं देता। प्रदेश में सरकार ने सत्ता संभालते ही गो सेवा आयोग बनाने का दावा किया था। इसमें कहा गया था कि लावारिस पशुओं के लिए गोशालाएं और काउ सेंक्युरी बनेंगी। लेकिन अभी तक जमीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसका उदाहरण हजारों भटकते लावारिस पशु हैं। उच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में प्रत्येक पंचायत में गोसदन खोलने के लिए सूबे की सरकार को आदेश दिए थे। लेकिन अभी तक इस पर सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार के तमाम दावों के बावजूद सड़कों पर लावारिस पशुओं की समस्या बढ़ रही है। इन पशुओं की संख्या

बढ़ने से सड़क पर दुर्घटना का अंदेशा भी बना रहता है। इतना ही नहीं चालकों को बाहन चालते समय उनको बचाने के लिए कई बार खुद दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। सत्तासीन सरकारें लावारिस पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कुछ नहीं करती हैं। हालत यह है कि जिला कुल्लू में करीब छह हजार गोवंश की संख्या है। सूबे में करीब 24 हजार लावारिस पशु सड़कों पर हैं। कंपकंपाती ठंड में इनकी हालत काफी खराब है। कई पशु ठंड और भूख के कारण बेमौत मर भी रहे हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन को इनकी हालत नहीं दिखाई देती।

## बोर्ड ने बकलोह के 235 डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को जारी किए नोटिस

## नोटिस

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

विद्युत बोर्ड ने बकलोह के अंतर्गत 235 डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को लंबित बिल चुकाने का नोटिस जारी किया है। इन उपभोक्ताओं ने बोर्ड के 7.72 लाख रुपये पर कुंडली मार रखी है। उपभोक्ता इस धनराशि को अदा करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इसको लेकर बोर्ड ने 235 उपभोक्ताओं को डिफॉल्टर घोषित किया है। इसके साथ ही इन उपभोक्ताओं को नोटिस जारी करके 15 दिन के भीतर लंबित बिल अदा करने के निर्देश दिए हैं। अगर नोटिस मिलने के बाद भी

## छात्रा से छेड़छाड़ मामले में आरोपी प्रधानाचार्य निलंबित

SUSPENDED

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

जिले के सरकारी स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले के आरोपी प्रधानाचार्य को डीम्ड सर्वेंट कर दिया गया। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इस म

# भारतीय कानून में क्या है रेप की कड़ी सजा, मिला है मृत्युदंड भी



किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें अपराध सिद्ध होने की दशा में दोषी को कम से कम पांच साल व अधिकतम 10 साल तक कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। कई मामलों में अदालत पर्याप्त और विशेष कारणों से सजा की अवधि को कम कर सकती है।

2012 के दिल्ली के निर्भया कांड के बाद संविधान संशोधन के जरिए आईपीसी की धारा 376 (ई) के तहत बार-बार बलात्कार के दोषियों को उप्रकैद या मौत की सजा का प्रावधान किया गया था। बोन्डे हाईकोर्ट ने बार-बार बलात्कार के दोषी को उप्रकैद या मौत की सजा देने के लिए आईपीसी की धारा में किए गए इस संशोधन की संवैधानिकता को बरकरार रखा।

भारतीय दंड सहिता की धारा 376 (ई) में संशोधन के तहत बार-बार बलात्कार का अपराध करने वाले दोषी को उप्रकैद या मौत की सजा हो सकती है। मुंबई अदालत ने शक्ति मिल्स सामूहिक बलात्कार कांड के तीन दोषियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए मौत



की सजा सुनाई थी। धारा 376 (ई) कहती है कि पहले अगर धारा 376, 376(ए), 376 (डी) के तहत आरोपियों को दोषी पाया जा चुका है। बाद में अगर फिर से उन्हें इनमें से किसी एक धारा में दोषी पाया जाता है तो सजा के तौर पर उन्हें उप्रकैद या मौत की सजा दी जाएगी।

रेप के अपराध को अलग-अलग हालात और श्रेणी के हिसाब से धारा 375, 376, 376 क, 376 ख, 376 ग, 376 घ के रूप में विभाजित किया गया है। ये हैं धारा 375 यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, उसे डरा धमका कर, दिमागी रूप से कमजोर या पागल महिला को धोखा देकर और उसके

शराब या पदार्थ के कारण होश में नहीं होने पर उसके साथ संभोग करता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा। अगर अदालत में रेप का आरोप साबित हो जाता है तो दोषियों को कठोर कारावास की अधिकतम सजा हो सकती है। आमतौर पर दोषी को कम से कम दस साल की सजा दी जाती है।

376 (क) धारा कहती है कि पति और पत्नी के अलग रहने के दौरान अगर पुरुष पत्नी के साथ संभोग करता है तो वो भी वे बलात्कार की श्रेणी में आता है। जिसके लिए दो वर्ष तक की सजा और जुर्माना देना पड़ेगा। 376 (ख) धारा के तहत आपके संरक्षण में रहने वाली किसी स्त्री के साथ संभोग भी इसी अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसके लिए पांच वर्ष तक की जेल के साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा।

376 (ग) धारा कहती है कि जेल में अधिकारी द्वारा किसी महिला बंदी से संभोग करना भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। जिसमें पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।

धारा 376 (घ) अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारी आदि से किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग करेगा तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। जिसकी सजा अवधि पांच साल तक हो सकती है।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा

कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी, 94180 25649

## ब्रेन हेमरेज (Brain Hemorrhage) के कारण

### द रीव टाइम्स ब्लूरो

हमारे शरीर में मस्तिष्क और नाड़ियों को प्राणवायु (Oxygen) और पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति रक्त वाहिकाओं से रक्त के द्वारा की जाती है। जिस तरह हृदय को रक्त की आपूर्ति न होने पर हृदयाधात्र आ जाता है, उसी प्रकार मस्तिष्क के कुछ हिस्से को 3 से 4 मिनिट से ज्यादा रक्त न मिलने पर प्राणवायु और पोषक तत्वों के आभाव में नष्ट होने लगता है, इसे ही मस्तिष्क का दौरा / Stroke या ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं।

### ब्रेन हेमरेज के कारण

ये अलग-अलग कारणों से होते हैं। स्ट्रोक की समस्या होने का सबसे अधिक खतरा तब होता है जब :

- व्यक्ति के शरीर का वजन अत्यधिक बढ़ जाता है।
- व्यक्ति की उम्र 55 साल या इससे अधिक होने पर।
- परिवार में किसी व्यक्ति को स्ट्रोक की समस्या होने पर।
- खराब जीवनशैली अपनाने पर।

### ब्रेन हेमरेज के प्रकार

इस प्रकार का स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क तक खून पहुंचाने वाली धमनियां अवरुद्ध या संकरी हो जाती है। इस्कीमिया होने पर रक्त का प्रवाह कम हो जाता है जिसके कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। धमनियों के अवरुद्ध होने का मुख्य कारण मस्तिष्क की धमनियों में रक्त का थक्का बनना होता है। धमनियों की दीवारों में प्लेक (plaque) जमा हो जाता है जिससे व्यक्ति को इस्कीमिया स्ट्रोक होने का खतरा रहता है।

### हेमरेजिक स्ट्रोक

यह स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क की धमनियों से खून का रिसाव होने लगता है या यह फट जाती है। खून रिसाव के कारण मस्तिष्क की कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है जिसके कारण ये कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। हेमरेज के बाद मस्तिष्क के ऊतकों में खून की सप्लाई नहीं हो पाती है।

### इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, हेमोरेजिक स्ट्रोक का एक सामान्य प्रकार है।

इस स्ट्रोक में मस्तिष्क की धमनियों के फटने के बाद मस्तिष्क के ऊतक खून से भर जाते हैं। सबाराकनॉइड हेमरेज, हेमोरेजिक स्ट्रोक का दूसरा प्रकार है और यह आमतौर पर कम होता है। इस प्रकार के स्ट्रोक में मस्तिष्क और उसके पतले ऊतकों के बीच के क्षेत्र में लीडिंग होने लगती है और पूरे क्षेत्र को घेर लेती है।

### ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक

टीआईए स्ट्रोक ऊपर बताए गए दोनों प्रकार के स्ट्रोक से अलग है क्योंकि इस प्रकार के स्ट्रोक में मस्तिष्क में खून का प्रवाह जरा सा ही गड़बड़ होता है। ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक, इस्कीमिक स्ट्रोक की तरह होता है क्योंकि यह आमतौर पर रक्त का थक्का बनने के कारण होता है।

### ब्रेन हेमरेज के लक्षण

भ्रम (confusion) की स्थिति उत्पन्न होना एवं बोतने और समझने में कठिनाई होना। सिरदर्द और उल्टी का अनुभव, चेहरे, पैरों और शरीर के एक हिस्से में सुन्नता महसूस होना, एक या दोनों आंखों से सही तरीके से

और स्पष्ट दिखायी न देना, टहलने में परेशानी एवं शरीर का संतुलन खो देना और चक्कर आना, मूत्राशय पर नियंत्रण न होना, हाथों व पैरों को हिलाने-डुलाने में दर्द होना एवं शरीर के तापमान में परिवर्तन होना, किंप्रेशन और आवाज लड़खड़ाना, शरीर कमजोर होना और लकवायस्त हो जाना, भावनाओं पर नियंत्रण न होना,

### ब्रेन हेमरेज से बचाव

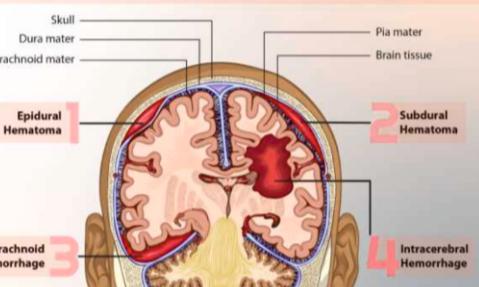
ब्रेन हेमरेज से बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि स्ट्रोक के कारणों को ही न उत्पन्न होने दिया जाये। जीवन शैली में बदलाव सहित अन्य एहतियात बरतकर स्ट्रोक से बचा जा सकता है। आइये जानते हैं स्ट्रोक से बचने के लिए क्या करें।

### संतुलित और स्वस्थ आहार लें।

अपने शरीर के वजन को नियंत्रित रखें। प्रतिदिन एक्सरसाइज करें। धूम्रपान और तंबाकू का सेवन न करें। शराब का सेवन कम मात्रा में करें।

अधिक जानकारी के लिए लिंक: hem.raj@iirdshimla.org

### Types of brain hemorrhage



कोलेस्ट्रोल न बढ़ने दें।

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें।

डायबिटीज न होने दें।

अनिद्रा की बीमारी हो तो इलाज कराएं।

संतुलित और स्वस्थ भोजन का अर्थ यह है कि फल, सब्जियां, होल ग्रेन, बादाम, अनाज, बीज भोजन में शामिल करें। रेड मीट न खाएं और कोलेस्ट्रोल एवं सैचुरेटेड फैट युक्त भोजन कम मात्रा में लें। रक्तचाप नियंत्रित रखने के लिए खाने में कम मात्रा में नमक का उपयोग करें।

डॉ. के आर शांडिल  
द रीव विलिनिक, शिमला

## A Push for Carbon Neutral Public Transport

December 2 is observed as 'National Pollution Control Day' so it is important that we do everything in our power to address the issue and take appropriate step to reduce our carbon footprints. Himachal took a constructive step towards this mission when Shimla was presented with 50 electric buses in February and the smaller-sized buses were added to the cavalcade recently. The bigger buses are estimated to cost around Rs 76 lakh, much higher price than the normal petrol-guzzling buses, but in the long run they will certainly have a positive impact on the environment.

The electric buses take just 30 minutes to charge and can move for hours with no carbon emissions; in addition to that, they cause low to no sound pollution, another added advantage. These buses have been added and are working smoothly and have made lives of people easier who earlier had limited options of public transport available to them.

But simply introducing a few of these electric buses on the road is not going to cut down the air pollution, the Government should start replacing the old buses as well.

The private bus operators are especially

expected to step up and take the responsibility of fighting climate change in their own small way. It is understandable that the high cost of these electric buses will act as a deterrent for the small bus operators to replace their old vehicles. But substituting the electric buses for the petrol-engine buses is extremely essential now. For this, the Government can provide a form of subsidy or loan to the private bus operators and support them in taking loans to buy these buses. The private business owners should have the foresight to know that gradually they will be saving the money on the cost of petrol/ diesel, and it

will also be a good return in terms of environmental conservation.

If some middle path is followed, then a day will not be too far when the roads of Himachal will have carbon-neutral public

transport and we will be able to set an example for the nation. Let us do everything in our capacity to prevent the air of Himachal from turning toxic as in Delhi. We still have some time in our hands, let's make the best use

# RECURRENCE OF ASSAULTS ON WOMEN - STRUGGLING FOR SOLUTION



After Nirbhaya incident, there have been a number of similar incidents which do come to limelight after the registration of FIR's, otherwise, the occurrence of such incidents is much more which usually go unreported.

In a country of Rama, Krishan, Mahavir, Buddha, and countless other such revered figures, the incidents of assaults on women are a curse especially in the modern age and the civilised society. It is the country which believes in "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः", referring to the honour and high status a woman is bestowed in Indian society, but the heinous crimes against women paint a starkly different picture.

Agitations by people, candle marches and the other forms of expressing anger are inevitable but we are at the same place as after the Nirbhaya episode. Post the incident, it was expected that legislative and administrative actions in future would evolve in a different

manner to curtail such incidents drastically. But there seems no improvement in this situation, the thrust of the people and society as whole always remained on hanging the culprit until death.

Here, we need to take into cognizance the following questions:

1. Why do we not think about aspects which discourage such incidents from happening? Do we have a proven action plan to control the impulses of the individuals? Need to find out the biological, physiological and psychological reasons behind and available yogic, ayurvedic and psychological solutions.
2. What action can we propose for the environmental concerns after addressing the human instinct? Environment plays a bigger role in stimulating or affecting basic human instincts. Do we have sound policy directives and implementation framework to check concerns of our life style and happenings surrounding us? Need to check our life style and modesty.
3. It is said that delayed justice is denied

justice. Why can't we ascertain that the cases of assault on women are brought to justice within the shortest possible period? Besides to ensure that the innocents are not victimised. Need to explore legislative measures.

Until a comprehensive action plan is in place on the above three aspects, we will be able to achieve nothing in spite of the magnitude of our anger and agitation. All these three areas comprise of detailed deliberation and a clear-cut strategy needs to be devised in this regard. The need of the hour is to brainstorm on the above parameters to come up with the commonly accepted agenda of implementation.

The development practitioners, academia, research institutions, administrative thinkers and the policy-makers need to prioritise the issue and allocate time for it in order to safeguard and empower our daughters, sisters, wife and mothers.

**Dr. L.C. Sharma**  
Editor-in-Chief

Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

## PARALI BURNING - A CONSPIRACY OR ENVIRONMENTAL EMPATHY

Crop stubble burning have been an age-old practice in India and across the globe. But never have this activity caused grave environmental concern until year 2016, leading to smog and barely breathable air quality. What was earlier restricted to two states, namely Punjab and Haryana have now affected majorly Delhi, Uttar Pradesh creating a dooms day situation.

According to an article published by the Indian Council of Social Science Research published in 1991, it was difficult to travel in rural areas of Punjab and Haryana at the end of September and early October because air used to be thick with the smoke of burning paddy straw. However, in recent year farmers have delayed the burning until late October. And this delay has played a major role and is responsible for the smog situation in Delhi and Uttar Pradesh. So, what has changed between 1991 and 2019?

The logical or call it an escapist reason is that of the wind flow patterns which primarily flows from the west during the monsoon season, but changes direction in October and starts blowing into Delhi from the north. They hue and cry that follow, showed government's 'ostrich mentality', instead of addressing the real cause and taking remedial measures, started providing happy seeders, paddy straw choppers, super straw management systems, rotavators etc to dispose the stubble. If the government data are to be believed, the ministry of agriculture gave Rs 269.4 crore, Rs 137.8 crore and Rs 148.6 crore respectively to Punjab, Haryana and Uttar Pradesh to manage the menace. Over and above this, in the month of November 2019, the apex court awarded additional price support of Rs 100 per quintal of paddy for this.

Did these measures help? Yes, but marginally. Haryana's smaller paddy footprint found it easier to monitor the situation. Whereas, Punjab, is finding it difficult to distribute stubble removing machines to farmers in time. But even with state subsidies, farmers of both states are finding it difficult to finance buying of equipment. However, Haryana has also been able to execute manage this to some extent. So, did all these measures stop the Parali burning menace effecting states like Delhi, Uttar Pradesh. NO!!

### The Real Reason

Until a few years ago, farmers in Punjab and Haryana burnt the remnants of the rice crops the smoke were confined to Punjab as they burnt the straw in late September and early October. However, in recent years, farmers have been delaying the burning until late October. The decision to delay was forced on farmers by the Punjab government, which passed the Punjab Preservation of Subsoil Water Act in 2009 (infamously known as "Monsanto Profit Act of 2009"). According to this law, farmers can sow rice only in the middle of June. The restriction meant that the fields would be harvested and cleared only in October by which time the direction of wind would have changed. Haryana too copied Punjab and passed a similar law. This delay is crucial and responsible for the smoke being carried all the way to Delhi

and Uttar Pradesh. Before this law was passed, the problem in Delhi were limited to vehicular and industrial pollution, apart from smoke from bonfires in winter, and there were no reports of the entire metropolitan being enveloped by smoke. If experts are to be believed, the legislation was passed ostensibly to preserve groundwater, the depletion of which was blamed on rice fields which supposedly used too much water and which were prone to evaporation, but this argument is a very tenuous one. According to the International Water Management Institute, water in rice fields contributes to recharging the groundwater and very little of it is lost to evaporation. The data from Uttar Pradesh in IWM's report too showed that rice fields in the state contributed to increasing the level of the water table, thus supporting the claim that water in rice fields replenishes the aquifers.

It is largely felt that the group that has been primarily responsible for exerting pressure to move away from growing rice in the name of "crop diversification" is the United States Agency for International Development (USAID). Which has a worldwide reputation of behaving like a front group for American multinational corporations such as Monsanto. It should, therefore, come as no surprise that Monsanto will be the primary beneficiary of USAID's purported solution for Punjab's problems. According to their solution, farmers need to stop growing rice and replace it with Monsanto's genetically modified (GMO) maize. The new law, reducing the time period during which farmers are permitted to grow rice, has further accentuated this problem. India's surplus food grain supply is an uncomfortable fact for Monsanto and other proponents of GMO food who insist that the world would face a shortage of food grains if not for genetically engineered plants sold by Monsanto. It's a known fact that in year 2012, the Punjab Chief Minister Prakash Singh Badal in collusion with Monsanto set up a research centre for creating maize seeds and announced plans to reduce the area under the cultivation of rice by around 45 percent in order to grow maize. Monsanto typically co-opts not only politicians but also members of the academia and converts them into its shills. The fear-mongering about the cultivation of rice reached a feverish pitch in the form of a campaign 'Chonne hetho rakba katao, Pani Bachao, Punjab Bachao (Reduce the area under rice, save water, save Punjab)' from a group of eminent scientists,

If the environmentalist and soil preservation experts are to be believed, Monsanto' fertilisers and pesticides are more or so responsible for receding water table in Punjab and Haryana as they have accumulated in the ground over the years leading to poor retention of moisture in the soil, forcing farmers to pump excessive amounts of underground water.

### Likeable Solutions

- The problems related to the low levels of groundwater and the inability of the soil to retain moisture must be solved, but the solution should not be a drastic one such as



creating famines by banning food items such as rice.

- Before the level of groundwater fell in Punjab and Haryana, the state experienced a problem of water-logging which was partially solved by pumping out the excess groundwater. Thus, it is clear that an acceptable level of the water table can be maintained by finding a proper balance between the two extreme situations.
- Burning the residual straw from the cultivation of rice is the cheapest method of clearing the fields. A ban on such burning will destroy the livelihood of small farmers and give way to industrial farming with a few large corporations owning all the land and resources. The government which has helped large corporations till now must not take any more steps that run the small farmers out of business.
- Government must help small farmers clear the fields between the rice and wheat seasons and implement proper water management solutions. This would mean going against the rules set forth by the World Trade Organisation which has mandated that no business other than American multinational corporations can receive aid or subsidies from the government, and any subsidy given to American businesses will be done under the cover of 'research grants' funnelled through universities. India should completely ignore these rules and fix its problems, not the least of which is the yearly phenomenon of smoke cover over Delhi.
- A step that should be taken immediately in order to prevent Delhi from becoming a gas chamber for several days every November, is to revoke what should rightfully be called the Monsanto Profit Act of 2009 and farmers should be allowed to sow their rice crop whenever they deem it fit to do

### Mission RIEV Intervention

Mission RIEV proposes inducting "Structured Intervention Programme (SIP)" that would educate and facilitate the farmers to change existing farm practices and adopt newer technologies and know-how in phased manner. This change can be seen without losing any competitive advantages and simultaneously achieving higher market returns, accessing risk free and readily available solution at the same operational cost. This would entail balance between preservation of environment, employability and sustainability amongst all stakeholders. The first step taken towards this was that of organising a conclave "Exploring Eco-friendly Sustainable Solution of Paralis Burning - In the states of Haryana and Punjab.

Mission RIEV has been invited by Government of Haryana to present, deliberate likeable solutions to resolve the 'Parali Burning' issue. We shall keep our readers updated.

**Anand Nair**, CEO, Flyers Group,  
anand@iirdshimla.org

# आगले जन्म मोहे विटिधा न कीजो

## देश में इंसानी शैतानों से सहमी महिलाएं... पर उम्मीद कायम रखें... संसद में प्याज़ पर चर्चा जारी हैं

नारी तुम केवल श्रद्धा हो.....जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां कोरे कागज़ पर एक बार हर नागरिक स्कूल या कॉलेज में लिखता-पढ़ता है। इसे समय-समय पर देश ने स्वीकार किया थी और ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर नारी को सम्मान दिया थी। वर्तमान में इन पंक्तियों पर संशय है क्योंकि यदि नारी श्रद्धा है तो आज बेटी इतनी सहमी और डरी हुर्दू क्यों है? क्यों उसे घर से बाहर स्वच्छंदता लिए आत्मसम्मान से जीने में डर लग रहा है? क्यों सनातनी परंपराओं से सुसज्जित इस देश में नारी उपभोग की वस्तु बनती जा रही है? क्यों उसके रक्षक मूक बनकर खड़े हैं? क्यों बच्ची स्वदूल जाने से डर रही है? क्यों महिला कार्यस्थल पर डरी-सहमी भय के माहौल में जी रही है? क्यों दिन छिपते ही उसे घर पहुंचने के लिए डर सता रहा है? क्यों उसकी आबू/इज्जत खेटे में है? क्यों, क्यों और क्यों?

हमारे देश के आकाऊं और सिपहसिलाओं के पास यदि इस क्यों का उत्तर है तो वो जनता के सामने सिर उठाकर आंख से आंख पिलाकर प्रतिउत्तर करें। अन्यथा स्वीकार करें कि नारी उपभोग की वस्तु ही है उनकी नज़र में और उसकी रक्षा करने में ये तथाकथित सरकारें और कानून असफल हो चुका है। आज जिस प्रकार से महिलाओं और बच्चियों को नोचा, खरोंचा, उधेड़ा जा रहा है उससे तो राम और श्रीकृष्ण की इस धरा को बलात्कारियों की सल्तनत कहा जाए तो इसमें कोई अतिश्योक्ति न होगी। क्या इस देश को औपचारिक रूप से महिलाओं के लिए असुरक्षित घोषित करने का समय आ गया है? विदेशों में तो भारत की ये छवि ही बन रही है। और यदि हालात यहां देखें तो ऐसा होना ही प्रतीत हो रहा है। घर से निकली बेटी घर वापिस आ भी जाएगी....इसमें संदेह है।

### निर्भया से गुड़िया और दिशा तक... बस खोफ ढी खोफ

7 वर्ष पहले राजधानी दिल्ली की बो घटना आज भी ताज़ा है। जिसने देशवासियों का दिल दहला दिया था। निर्भया को किस प्रकार नोच-नोच कर तोड़ा गया था, इतना वीभत्स कि रुह कांप जाए। रेप के बाद उसे जिस प्रकार घोर प्रताड़ना के बाद मारा गया, उससे तो शैतान की रुह भी कांप जाए। देश भर में मोमबत्ती जुलूस, विरोध प्रदर्शन हुए और एक लंबे समय तक होते भी रहे लेकिन अब विरोध की आंच धीमी हो गई है और दरिंदों की दया याचना टेबल से टेबल पर धूम ही रही है। जिस बेटी को इतनी कूरता से बलात्कार कर जघन्यता से मारा गया, उसे 7 वर्ष से अधिक समय हो गया है और हैवान सरकारी रोटियां तोड़कर अभी भी स्वच्छंदता से सांस ले रहे हैं।

फांसी के इंतज़ार में वो कोख़ भी दर-दर रो रही है जिसने उस पूल सी निर्भया को जन्म दिया था।

शांत और ठंडा प्रदेश कोटखाई गुड़िया रेप और मर्डर के बाद उबल गया और उस स्कूल की बच्ची को इंसाफ के लिए प्रदर्शनों और जूलूसों का एक लंबा दौर चला। गुड़िया एक मासूम सी बच्ची, स्कूल से घर जाते समय अगवा की गई और उसके बाद उसका न केवल बलात्कार किया गया बल्कि इतनी बूरी तरह से तोड़ा-मरोड़ा गया कि उसकी वो वीभत्स तस्वीरें किसी के भी दिल से नहीं मिल सकती। क्या गुलती थी उस बच्ची की? लगातार रेप के बाद उसे मार दिया गया और उसके जननांगों पर मिट्टी से साथ्यों को मिटाकर तांदी जंगल में तोड़-मरोड़ कर फेंक दिया गया। पूरा हिमाचल इसका विरोध करता रहा, कितनी ही संस्थाओं ने आगे आकर सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन कर रहां की सोई पुलिस और प्रशासन को जगाया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बेहद शर्मनाक था, और ऐसी उम्मीद किसी ने भी नहीं रखी होगी कि समाज के रक्षक ही जांच के दायर में आ जाएंगे। हिमाचल पुलिस ही इस केस में जांच और शक के दायरे में आ गई जिससे पुलिस विभाग के आला अधिकारी जेल में चले गए। एक के बाद एक गुलती को छुपाने के लिए पुलिस ने बड़ी गुलतियां की और लॉकअप में ही सूरज की हत्या के



बाद जांच ही बदल गई। पहले किसी के स्कैच पुलिस ने वैबसाइट पर डाल दिये और बाद में उन्हें हटाकर नेपालीयों को पकड़ लिया। फिर लॉकअप में ही हत्या हो जाने के बाद पुलिस पूरी तरह से शक के दायरे में ही गई और लोगों का विश्वास ही कानूनी प्रक्रिया से उठ गया। सीबीआई जांच भी बहुत अधिक कुछ नहीं निकाल पाई और एक चिरानी को इसका गुनहगार बताकर वो भी चलती बनी। अब फोरेसिक जांच में एक के अलावा कई लोगों के होने की आशंका के बाद इंसाफ के लिए सार्थक कदम उठाने की पहल ही नहीं की जा रही है। यानि उस बच्ची को इंसाफ मिला या नहीं यह संदेहास्पद ही है। लोग आज भी इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं पर शायद अब अधिक उम्मीद करना स्वयं से बेमानी ही होगी। गुड़िया की चीखें आज भी कानों को कचाटती हैं। उस बच्ची को इंसाफ मिल गया है यह बात किसी को भी सही नहीं लगती और शायद लगनी भी नहीं चाहिए। सच्च मूक है और जंगल शोर करके उसे बताने लिए आतुर भी। लेकिन उसे सुनना कोई नहीं चाहता है। क्या अपराधी बेखौफ होकर धूम

को इंसाफ है?....यह प्रश्न इस पूरे घटनाक्रम की नींव है लेकिन नींव तो अंधेरे में होती है...इस गुड़िया प्रकरण की तरह ही....

तेलंगाना में युवा डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत ने पूरे देश को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया। हालांकि इस बीच ऐसे ही कितने मामले हृदयविदारक रहे लेकिन ताज़ातरीन घटनाक्रम में यह इंसानियत को हिलाकर रख दिया। चार युवकों ने किस प्रकार पहले उस डॉक्टर युवती को अगवा किया, गैंगरेप किया, उसे कूरता से प्रताड़ित कर एक पुलिया के नीचे अधजला छोड़कर भाग गए। इस वीभत्स तस्वीर को पूरा देश देखकर विचलित हो गया। इंसाफ के लिए देश भर में आंदोलन होने लगे और यह लगभग तय हो गया अपराधियों को अब किसी का डर नहीं है। बेटियों को अब सुरक्षित रख पाना सरकार के बस की बात नहीं है। इसी बीच तेलंगाना पुलिस की सुबह तड़के ही यह खबर कि चारों अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, देश भर को एक राहत भरी खबर बन कर आई। पुलिस आधी रात को उसी स्थान पर जहां हुन्होंने उस युवती को जलाया था, लेकर गए और वैसा ही सीन रिक्रियेट



करते समय एक अपराधी ने पुलिस की बंदुक छीन कर गोली चलाई तो बदले में एनकाउंटर में पुलिस ने चारों को भग्नाड़ा बताकर मार दिया। यहां यह दीगर बात है कि इस समाचार को सुनते, पढ़ते ही देश में सबने इस घटना पर जश्न मनाया, जबकि सबसे पहले एक महिला मंत्री ने इसका विरोध किया और इसे

### उभरते भारत पर बलात्कारी भारत का कलंक... असहनीय

गुलत बताया। विपक्ष को मौका मिला तो संसद में विपक्ष भी इस पर सवाल उठाने लगे। जब तक इंसाफ नहीं मिला था तो यही संसद थी जिसमें सभी एक मत से कड़ी से कड़ी सजा देने के हक़ में थे और लोगों की संवेदनशीलों के साथ बहते जा रहे थे। जैसे ही एकशन हुआ तो उस पर उंगलियां उठा दी। दोगली



मानसिकता के साथ हमारे प्रतिनिधि न तो सख्त कानून ही बनने दे रहे हैं और न ही लोगों को सांत्वना देने से बाज आ रहे हैं। ऐसे में यहां यह कहना ग़लत न होगा कि यदि अपराधियों ने पुलिस पर ही गोली चलाई है तो उनका एनकाउंटर होना पुलिस की जीत है और इंसाफ भी। घटनाक्रम कुछ भी हो, उस निर्मता को याद किया जाए जब तक रेप और गैंगरेप और ज़िंजा जलाने की तस्वीर सामने आती है तो यह सजा भी कम ही लगती है।

उसके बाद उन्नाव के साथ-साथ भारत से जगह-जगह से बलात्कार की घटनाएं सामने आती गई और सरकार कानून बनाने की बात करती रही है। आज देश में प्रतिसेकंड के हिसाब से बेटी को कुचला-मसला जा रहा है। हम आंकड़े एकत्रित करने में लगे हुए हैं। उन्नाव में तो 90 प्रतिशत तक छुलसी पीड़िता ने आखिर अस्पताल में दम तोड़ दिया और उसके बाद यूपी सहित देशभर में सियासत तेज़ हो गई।

### रंग-बिल्ला से धनंजय और दिशा तक सरकारों की उठापोह

आज से लगभग 40 वर्ष पहले वहां बार रेप जैसे जग्न्य अपराध में फांसी हुई थी। उस दौर में दो कुख्यात अपराधी कुलजीत सिंह ऊर्फ़ रंग और जसवीर सिंह ऊर्फ़ बिल्ला ने एक सैन्य अधिकारी के दो बच्चों को अगवा किया और उनका मर्डर कर दिया। जिसमें लड़की का रेप भी होने की पुष्टि हुई थी। गीता और संजय चौपड़ा जब आकाशवाणी दिल्ली में युववाणी कार्यक्रम में प्रस्तुति के लिए जा रहे थे तो रंग और बिल्ला ने उन्हें गाड़ी में बिठाया और पहले गीता को मार दिया और फिर गीता का रेप कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। ऐसा बताया गया कि जब उसके भाई संजय को मार दिया गया तो उसके बाद उसे उसके भाई गीता के रेप कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। ऐसा बताया गया कि जब उसके भाई गीता को मार दिया तो उसके बाद उसे उसके भाई गीता के रेप कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। ऐसा बताया गया कि जब उसके भाई गीता को मार दिया तो उसके बाद उसे उसके भाई गीता के रेप कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। ऐसा बताया गया कि जब उसके भाई गीता को मार दिया तो उसके बाद उसे उसके भाई गीता के रेप कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। ऐसा बताया गया कि जब उसके भाई गीता को मार दिया तो उसके ब



## उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 218 त्वरित अदालतों के गठन का निर्णय लिया

द रीव टाइम्स ब्लूरो

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु 218 त्वरित अदालतों के गठन का निर्णय लिया है। प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक के अनुसार, इनमें से 144 अदालतें दुष्कर्म के मामलों की नियमित रूप से सुनवाई करेंगी जबकि 74 अदालतों में पोक्सों के मामले सुने जाएंगे। प्रदेश के कानून मंत्री के अनुसार, इन सभी अदालतों हेतु अपर सत्र न्यायाधीश के



218 पद सुनित किए जाएंगे। अदालत कर्मियों के भी पद बनाए जाएंगे। इन अदालतों के गठन पर होने वाले खर्च का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार तथा 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार उठाएंगे।

## सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल संरक्षित क्षेत्र में निर्माण पर लगी रोक हटी दी



द रीव टाइम्स ब्लूरो

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ताजमहल संरक्षित क्षेत्र में सभी तरह के निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर लगी रोक हटा दी है। सुप्रीम

## सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया

सशस्त्र सेना झंडा दिवस



7 दिसम्बर - 7 DECEMBER  
ARMED FORCES FLAG DAY

मनाया जाता है। सरकार ने साल 1993 में संबंधित सभी फंड को एक सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में समाहित कर दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की रक्षा समिति ने युद्ध दिग्गजों तथा उनके परिजनों के कल्याण हेतु 07 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाने का फैसला लिया था।

इस दिवस को मनाने की शुरुआत 07 दिसंबर 1949 से हुई थी। साल 1949 से प्रत्येक साल 07 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस

द रीव टाइम्स ब्लूरो



विश्वभर में अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के बारे में लोगों के बीच जागरूकता

## नागरिकता (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पारित

द रीव टाइम्स ब्लूरो

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 आधिकारिक 09 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पारित हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सदन में पेश इस विधेयक को 311-80 मतों के अंतर से पारित किया गया। इस विधेयक पर 12 घंटे से भी अधिक समय तक बहस चली तथा आखिर इसे पारित किया गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक 1950 के नेहरू लियाकत समझौते की गलती को सुधारने के लिए लाया गया है। इस बिल के मुताबिक, नागरिकता प्रदान



करने से जुड़े नियमों में बदलाव होगा तथा अवैध प्रवासियों को बैगर दस्तावेज के नागरिकता मिलेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि नागरिकता संशोधन बिल सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है।

## सब लेफिनेंट शिवांगी बनीं भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट



द रीव टाइम्स ब्लूरो

सब-लेफिनेंट शिवांगी हाल ही में भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट के रूप में

शामिल हुई। उन्होंने कोच्चि नवल बेस पर ॲपरेशनल ड्यूटी जॉइन की। नौसेना के अधिकारियों के अनुसार, शिवांगी ड्रेनियर सर्विलांस एयरक्राफ्ट उड़ाएंगी। भारतीय नौसेना अकादमी में शिवांगी को 27 एनओसी कोर्स के तहत एसएसी (पायलट) के रूप में शामिल किया गया था। वाइस एडमिरल ए. के. चावला ने जून 2018 में औपचारिक तौर पर उन्हें कमीशन किया था। शिवांगी विहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं।

## सऊदी अरामको ने दुनिया के सबसे बड़े आईपीओ की घोषणा की

द रीव टाइम्स ब्लूरो

हाल ही में सऊदी अरामको आईपीओ से पैसे जुटाने के मामले में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अरामको के बाद चीन की अलीबाबा ने आईपीओ से सबसे ज्यादा पैसे जुटाए हैं। अलीबाबा ने साल 2014 में 25 अरब डॉलर जुटाए थे। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको विश्व की सबसे अहम तेल कंपनियों में से एक है।



أرامكو السعودية  
"saudi aramco"

अरामको कच्चे तेल की सबसे बड़ी नियर्यातक है। सऊदी अरामको के कूड़ ऑयल फैसिलिटी सेंटर्स पर हाल ही में ड्रोन हमला हुआ था।

## नीरव मोदी- विजय माल्या के बाद दूसरा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित



द रीव टाइम्स ब्लूरो

विजय माल्या के बाद नीरव मोदी दूसरा ऐसा कारोबारी है जिसे नए भगोड़ा आर्थिक

अपराधी अधिनियम 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी करार दिया गया है। विजय माल्या को इससे पहले इसी अधिनियम के तहत आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। नीरव मोदी एवं उसका मामा मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से करीब 14,000 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा करने के मामले में मुख्य आरोपी हैं।

नीरव मोदी के खिलाफ फरवरी 2017 में घोटाले से संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।

## सुंदर पिचाई बने अल्फावेट के सीईओ

द रीव टाइम्स ब्लूरो

कंपनी ने गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज ने सीईओ पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद यह फैसला लिया है। सुंदर पिचाई ने इंटरनेट की दिग्गज कंपनी के सह-संस्थापक लैरी पेज की स्थान लेंगे। इस प्रमोशन के साथ ही सुंदर पिचाई विश्व के सबसे शक्तिशाली कॉर्पोरेट नेताओं में से एक बन गए हैं। उन्होंने अप्रैल 2004 में गूगल ज्वाइन किया था। उन्होंने गूगल सीईओ का पद ग्रहण 02 अक्टूबर 2015 को किया था।

मैनेजमेंट और इनोवेशन पर काम करना शुरू किया था। उन्होंने जीमेल और गूगल मैप्स के डेवेलपमेंट में भी काम किया। सुंदर पिचाई ने गूगल सीईओ का पद ग्रहण 02 अक्टूबर 2015 को किया था।

## प्रियंका चोपड़ा को मिला यूनिसेफ का मानवतावादी पुरस्कार



द रीव टाइम्स ब्लूरो

जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने 2019 के पुरस्कार विजेता के तौर पर प्रियंका चोपड़ा के नाम की घोषणा की थी। प्रियंका चोपड़ा न केवल मनोरंजन

और फैशन की दुनिया में बल्कि सामाजिक कार्यों में भी काफी सक्रिय हैं। डेनी काये को साल 1974 में लायंस क्लब से मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डेनी काये का 03 मार्च 1987 को निधन हो गया। प्रियंका चोपड़ा पिछले 15 सालों से सदूभावना राजदूत के रूप में यूनिसेफ से जुड़ी हुई है।

अब उन्हें उनके काम हेतु यूनिसेफ के डेनी काये मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

## संसद भवन की कैंटीन में अब नहीं मिलेगा सस्ता खाना

द रीव टाइम्स ब्लूरो

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, संसद में सांसदों को भोजन पर दी गई छूट को अब जल्द ही समाप्त किया जा सकता है। अब, सांसदों को भोजन की लागत के अनुसार भुगतान करना होगा। पिछले लोकसभा के दौरान कैंटीन में खाद्य मूल्य में वृद्धि की गई थी और सब्सिडी बिल को कम किया गया था। संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी बहुत बार विवादों का हिस्सा रही है। हाल ही में, संसद की कैंटीन की रेट लिस्ट भी वायरल हुई थी।



देखा गया है कि, सब्सिडी के तहत देश के सांसदों के संसद की कैंटीन में खाना बहुत कम दाम पर मिलता था।

## कैबिनेट ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी



द रीव टाइम्स ब्लूरो

कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी दी है। इस बिल के अनुसार, नागरिकता प्रदान करने से जुड़े नियमों में बदलाव होगा तथा अवैध प्रवासियों को बैगर

दस्तावेज के नागरिकता मिलेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि नागरिकता संशोधन बिल सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। नागरिकता संशोधन विधेयक में नागरिकता कानून, 1955 में संशोधन का प्रस

## पाक प्रधानमंत्री के बाद सुर, क्षेत्रीय सहयोग को बताया अहम

द रीव टाइम्स ब्लूरो

कश्मीर मसले पर विश्व समुदाय के जवाब से मुंह की खाने के बाद इमरान खान के सुर बदलते दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि क्षेत्रीय विकास के मामले में पाकिस्तान क्षेत्रीय सहयोग की ताकत में यकीन रखता है। इमरान ने 35वें दक्षेस घोषणा-पत्र दिवस पर अपने संदेश में यह बात कही। सनद रहे कि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से इमरान ने परमाणु जंग की धमकी दी थी।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का मानना है कि नतीजा देने वाला क्षेत्रीय

सहयोग दक्षेस के घोषणा-पत्र में निहित सिद्धांतों के अनुपालन से ही हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आठ दिसंबर ही वह दिन है जब नेताओं ने दूरदर्शिता के साथ दक्षेस घोषणा-पत्र को अपनाया था। नेताओं ने दक्षिण एशिया की प्रगति और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का संकल्प व्यक्त किया था। इमरान ने यह भी कहा कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें डॉडी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमसे अपेक्षाएँ हैं कि हम गरीबी, अशिक्षा और अधूरे विकास की समस्याओं का निदान करेंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आठवां सदस्य राष्ट्र बना था।

## अमेरिका और ईरान ने मुक्त किए एक-दूसरे के नागरिक रिहट्जरलैंड ने निभाई मध्यस्थ की भूमिका

द रीव टाइम्स ब्लूरो

अमेरिका और ईरान के रिश्तों में तल्खी और तनाव पैदा करने वाले बयानों और प्रतिवांधों से इतर भी 'कुछ' चल रहा है। इसी का नतीजा है कि शनिवार को दोनों देशों ने



अपने यहां कैद एक-दूसरे के नागरिकों को आजाद किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में कैदियों की ऐसी अदला-बदली की घटना अप्रत्याशित मानी जा रही है। ट्रंप

2015 में अपने चुनाव प्रचार के समय से ही ईरान के खिलाफ लगातार आग उगलते रहे हैं। कुछ महीने पहले हालात युद्ध वाले भी बन गए थे।

ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी नागरिक शीघ्र वांग को ईरान से मुक्त किया गया है। जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया बीजिंग में जन्मा वांग तीन साल से ईरानी जेल में कैद था। जबकि

## दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनीं फिनलैंड की सना मरीन, एंटी रिने की ली जगह

द रीव टाइम्स ब्लूरो

फिनलैंड में 34 साल की सना मरीन नई प्रधानमंत्री बनी हैं। वह फिनलैंड के इतिहास के साथ वर्तमान में दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री भी बन गई हैं। बता दें कि एंटी

## आंध्र प्रदेश सरकार ने 'दिशा' बिल को मंजूरी दी



द रीव टाइम्स ब्लूरो

आंध्र प्रदेश सरकार ने दुष्कर्म के दोषियों को जल्द सजा देने हेतु 11 दिसंबर 2019 को एक 'दिशा' बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल में दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई 21 दिन में पूरी कर सजा देने का प्रावधान किया गया है। इस बिल में आईपीसी की धारा 354 में संशोधन करके नई धारा 354 (ई) बनाई गई है।

बिल के पास होते ही आंध्र प्रदेश दुष्कर्म के मामलों में मौत की सजा देने वाला पहला राज्य होगा। यह कानून, आंध्र प्रदेश अपराध कानून में एक संशोधन होगा। इसे 'आंध्र प्रदेश दिशा कानून' नाम दिया गया है।

## डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग लोकतंत्र समर्थक बिल पर किए हस्ताक्षर, जाने हांगकांग संघर्ष क्या है?

द रीव टाइम्स ब्लूरो

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल के अतिरिक्त एक और बिल पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस बिल के मुताबिक, भीड़ को नियंत्रित किए जाने हेतु प्रयोग में लिए जाने वाले आंसू गैस, रबर बुलेट या स्टन गन इनके निर्यात पर प्रतिवंध लगा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 नवंबर 2019 को हांगकांग में लोकतंत्र की मांग के लिए चल रहे प्रदर्शनों का समर्थन करने संबंधी एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद अब यह बिल कानून बन

गया है। यह कानून मानव अधिकारों के उल्लंघन पर प्रतिवंधों का प्रकाश डालता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल के अतिरिक्त एक और बिल पर भी हस्ताक्षर किए हैं। यह बिल हांगकांग पुलिस को मिलने वाले असला-बारूद को प्रतिवंधित करने से जुड़ा है। इस बिल के मुताबिक, भीड़ को नियंत्रित किए जाने हेतु प्रयोग में लिए जाने वाले आंसू गैस, रबर बुलेट या स्टन गन इनके निर्यात पर प्रतिवंध लगा दिया गया है।

विधेयक के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति

## चीन ने अमेरिकी राजनयिकों पर लगाई जवाबी पांचदियां अमेरिका ने भी लगाए थे चीनी राजनयिकों पर प्रतिबंध

द रीव टाइम्स ब्लूरो

अमेरिका में अपने राजनयिकों पर बंदिशें लगाए जाने के बाद चीन ने भी जवाबी कार्रवाई की है। उसने अपने यहां अमेरिकी राजनयिकों पर कई तरह की पांचदियां लगा दी हैं। चीन ने बताया कि देश में अमेरिकी राजनयिकों के खिलाफ कई कदम उठाए गए हैं। उन्हें स्थानीय अधिकारियों से मिलने से पहले अब विदेश मंत्रालय को सूचित करना होगा। अमेरिका ने भी गत अक्टूबर में चीनी राजनयिकों को आदेश दिया था कि वे अमेरिका में किसी अधिकारी से मिलने और किसी कहलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने से पहले विदेश मंत्रालय को सूचित करेंगे।



पांचदियों के जवाब में उठाया गया है। हम फिर यह आग्रह करते हैं कि अमेरिका अपनी गलतियों को सुधार ले और नियमों को रद कर दे। अमेरिका ने चीन के इस कदम को पारस्परिक करार दिया है। प्रवक्ता चुनियंग के अनुसार, अमेरिकी राजनयिकों को किसी चीनी अधिकारी से मिलने के बारे में विदेश मंत्रालय को पांच कार्य दिवस पहले सूचना देनी होगी।

## चीन में खुली तीन ई-कोर्ट जहां रोबोट सुना रहे हैं फैसला

द रीव टाइम्स ब्लूरो

चीन ने न्यायिक अदालतों का बोझ कम करने के लिए ई-कोर्ट खोलकर दुनिया भर खासकर भारत के लिए मिसाल कायम की है। चीन के हेंगजाऊ शहर में अगस्त 2017 में पहले इंटरनेट कोर्ट की स्थापना की गई थी। जहां पहले ही महीने में 12074 मामले आए, जिनमें से 10391 का निपटारा भी हो गया था।



इन कोर्ट में पेशी भी वीडियो चौट के माध्यम से हो सकती है। सुनवाई और जिरह खत्म होने के बाद फैसला भी ऑनलाइन ही मिल जाता है। इस कोर्ट में ऑनलाइन कारोबार के विवाद, कॉर्पोरेट के मामले, ई-कॉर्मस प्रोडक्ट के दावों के मामले सुने जा रहे हैं। इस कोर्ट में सबसे ज्यादा मामले मोबाइल हुईं और उन्हें परिवहन और संचार मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया।

## साझा भारत अफ्रीका की जोजिबिनी के सिर सजा भिस्स यूनिवर्स 2019 का रिताब

द रीव टाइम्स ब्लूरो

दीप्ति अफ्रीका की जोजिबिनी टॉपी ने साल 2019 का भिस्स यूनिवर्स खिताब जीत लिया है। अमेरिका के जॉर्जिया अटलांटा में हुई इस प्रतियोगिता में दुनिया भर से 90 लड़कियों ने हिस्सा

दस में कोलंबिया, फ्रांस, आइसलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको, पेरू, पुएर्टो रिको, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और लियो भी प्रतियोगिता में शुरू हो जाती है। चीन के सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वी-चौट पर मोबाइल कोर्ट का भी विकल्प दिया गया है। जिसके जरिए चीन ने अपने नागरिकों को अदालत में शारीरिक रूप से पेश हुए बिना मामले की सुनवाई और इंसाफ की सुविधा प्रदान कर रहा है।

अमेरिका की सुंदरियों जगह बनाई। भारत की तरफ से वर्तिका में हिस्सा लिया लेकिन वह शीर्ष दस में जगह नहीं बना पाई। 26 साल की जोजिबिनी लैंगिक भेदभाव के खिलाफ सक्रिय तौर पर खड़ी होने वाली एक्टिविस्ट के तौर पर भी जाना जाती है। वह सोशल मीडिया पर लिंग संबंधी रुद्धियों के खिलाफ कैपेन भी चला चुकी हैं। जोजिबिनी के साथ 20 सुंदरियां सेमीफाइनलिस्ट तक पहुंची थीं। शीर्ष 20 सुंदरियां सेमीफाइनल तक पहुंची थीं। शीर्ष लड़कियों में जिरह नहीं बना पाई।

### स्वीडन के 16वें नरेश कार्ल गुस्ताफ पांच दिवसीय भारत दौरे पर, भारत-स्वीडन के बीच हुए तीन समझौते

द रीव टाइम्स ब्लूरो

स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ सोलहवें एयर इंडिया के विमान से भारत दौरे पर पहुंचे। उनके साथ पत्नी सिल्विया भी मौजूद थीं। ऐसा पहली बार हुआ, जब शाही जोड़े ने किसी देश की सरकारी यात्रा हेतु कमर्शियल प्लाइट का उपयोग किया। स्वीडन के राजा कार्ल सोलहवें गुस्ताफ तथा रानी सिल्विया हाल ही पांच द

# करंट अफेयर्स

THE  
CURRENT  
AFFAIRS  
2019

- विश्व मुदा दिवस जिस दिन मनाया जाता है - 05 दिसंबर
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को और जितने साल हेतु बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है - 10 साल
- वह राज्य सरकार जिसने स्कूली छात्रों के लिए 'मधु ऐप' लांच की - ओडिशा सरकार
- इंडैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान का यह नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया तथा वे 1981 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 43 रन देकर 8 विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं - बॉब विलिस
- भारतीय मूल की डेमोक्रेटिक सांसद का यह नाम है जिन्होंने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से अपना नाम वापिस ले लिया है - कमल हैरिस
- आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है - 5 प्रतिशत
- अंतर्राष्ट्रीय वालंटियर दिवस जिस दिन मनाया जाता है - 5 दिसंबर
- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मालदीव को भारत में निर्मित जो तटरक्षक जहाज उपहार स्वरूप दिया गया है - कामयाब
- हाल ही में जिस देश ने पराली (फसल अवशेष) जलाए जाने से उत्पन्न समस्या दूर करने हेतु एक स्वीडिश तकनीक का परीक्षण किया है - भारत
- जिस राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर हर साल 10 दिवसीय हॉन्निबल महोत्सव का आयोजन किया जाता है - नागलैंड
- विजय माल्या के बाद जिसे हाल ही में आर्थिक अपराध के तहत भगौड़ा घोषित किया गया है - नीरव मोदी
- भारत सरकार ने तमिलनाडु के चुने हुए शहरों में पानी की आपूर्ति और सीधेरेज के बुनियादी ढाँचे को विकसित करने के लिए भारत सरकार ने जिस संस्था के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये - एशियाई विकास बैंक
- हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में जिस स्थान पर हैं - पांचवें
- RBI की पांचवीं द्विमासिक नीति समीक्षा के दौरान भारत की रेपो रेट यह रखी गई है - अपरिवर्तित (5.15 प्रतिशत)
- इसरो ने जिस राज्य के कुलसेकरपट्टिनम के पास थूकुड़ी में अपने दूसरे अंतरिक्ष केंद्र के लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है - तमिलनाडु
- अलीबाबा को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कंपनी जो बनी - अरामको
- जिस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ के 'डैनी काये मानवतावादी

- 'पुरस्कार' से सम्मानित किया गया - प्रियंका चोपड़ा
- भारत और जिस देश के बीच 'इंद्र अभ्यास' का आयोजन हाल ही में किया जायेगा - रूस
- केंद्र सरकार ने पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना और सुदृढीकरण हेतु 'निर्भया फंड' से जितने करोड़ रुपये मंजूर किए हैं - 100 करोड़ रुपये
- केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जिस राज्य में अवंती मेंगा फूड पार्क का उद्घाटन किया - मध्य प्रदेश
- गूगल की मूल कंपनी का यह नाम है हाल ही में जिसके सीईओ सुदर पिचाई बने हैं - अल्फाबेट
- स्वीडन के शासक का यह नाम है जो हाल ही में पांच - दिवसीय भारत यात्रा पर आये - कार्ल XVI गुस्ताफ
- हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के निविरोध अध्यक्ष जिसे चुना गया - लालू प्रसाद यादव
- अमेरिका ने जिस देश को हाल ही में 10 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता राशि दी है - लेबनान
- भारत और स्वीडन के बीच हाल ही में जितने समझौते पर हस्ताक्षर किये गये - तीन
- भारतीय नौसेना दिवस जिस दिन मनाया जाता है - 04 दिसंबर
- FSSAI द्वारा हाल ही में जिस रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम 'ईट राईट स्टेशन' प्रमाणित किया गया है - मुंबई सेंट्रल
- हाल ही में रूस और जिस देश ने पावर ऑफ साइबरिया नामक क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया - चीन
- हाल ही में वह देश जो 'मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा' लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है - ऑस्ट्रेलिया
- कर्नाटक क्रिकेट टीम ने तमिलनाडु टीम को एक रन से मात देकर लगातार जितनी बार सैयद मुश्तक टी - 20 टूर्नामेंट ट्रॉफी जीत ली है - दूसरी बार
- वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसने हाल ही में 'बैलन डी ऑर' पुरस्कार जीता है - लियोनेल मेसी
- पुस्तक 'अर्ली इंडियंस' द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी कम फ्रॉम' के लेखक हैं जिन्होंने हाल ही में शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज जीता है - टोनी जोसेफ
- चीन की सिचुआन एयरलाइन ने हाल ही में जिस देश के लिए मालवाहक विमान सेवा शुरू की है - भारत
- रेटिंग इंजेसी क्रिसिल ने 2019-20 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 6.3 फीसदी से घटाकर जितने फीसदी किया है - 5.1 फीसदी
- वह देश जिसने हाल ही में अमेरिकी सेना और गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है - चीन
- विश्व विकलांगता दिवस जिस दिन मनाया जाता है - 03 दिसंबर
- जिस भारतीय मूल के इंजिनियर की जानकारी के आधार पर हाल ही में नासा ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर का पता लगाया है - शनमुग सुब्रमण्यन
- कर्नाटक के जिस तेज गेंदबाज ने टी 20 मैच में 1 ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं - अभिमन्यु मिथुन
- भारत और जिस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सूर्य-किरण-XIV' का आयोजन हाल ही में किया जाएगा - नेपाल
- हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने जिस राज्य की जननायक जनता पार्टी (JJP) को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया - हरियाणा
- केंद्र सरकार ने जिस राज्य में लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है - मणिपुर
- जिसने हाल ही में 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है - सोमा रौय

- जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है - 02 दिसंबर
- विश्व एड्स दिवस जिस दिन मनाया जाता है - 01 दिसंबर
- नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए सरकार द्वारा जो कार्यक्रम आरंभ किया गया है - मिशन इन्ड्रधनुश 2.0
- मलयालम के जिस कवि ने साहित्य जगत में उत्कृष्ट योगदान हेतु 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है - अविक्तम अच्युतन नंबूदरी
- विश्व भर में जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है - 10 दिसंबर
- वह विभाग जिसमें गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कर्मचारी खादी यूनिफार्म पहनेंगे - अर्धसैनिक बल
- यूनाइटेड नेशंस डिवेलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक - 2019 में भारत की रैंकिंग है - 129
- इस स्थान को डब्ल्यूटीए अवार्ड्स में विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है - आवृ धादी
- हिंदी कवि जिन्हें हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है - विश्वनाथ प्रसाद
- भारतीय वायुसेना प्रमुख जिनके नाम पर 30 राफेल विमानों के टेल नंबर जारी किये जायेंगे - बीएस धनोआ
- स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों की खरीद में बढ़ातरी हुई है - 5 प्रतिशत
- भारत और चीन के बीच आरंभ हुए द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास का नाम है - हैंड-इन-हैंड
- वह देश जिसपर वाडा द्वारा आगामी चार सालों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है - रूस
- संयुक्त अरब अमीरात और जिस देश के मध्य हाल ही में आयरन यूनियन - 12 नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया - अमेरिका
- हाल ही में जो पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर नया देश बन गया है - बोगानविले
- पाकिस्तान में 2019 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए गए लोगों की टॉप - 10 सूची में जितने भारतीय शब्दिल हैं - 3
- हाल ही में जिस ओपनर क्रिकेटर ने 174 गेंदों में रणजी ट्रूफी के इतिहास का तीसरा सबसे तेज दोहरा शतक जड़ दिया है - पृथ्वी शॉ
- हाल ही में ओडिशा सरकार ने 'कलिया योजना' के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि को 10,000 रुपए से घटाकर जितने रुपए कर दिया है - 4,000 रुपए
- टाइम मैगजीन ने साल 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर जिसे चुना है - ग्रेटा थनबर्ग
- भारत और जिस देश के बीच 'इंद्र अभ्यास' का आयोजन हाल ही में किया जा रहा है - रूस
- जिसे हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत किया गया है - अबी अहमद अली
- प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है - 11 दिसंबर
- केंद्र सरकार के अनुसार जिस योजना के तहत अब तक 10 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की तीन शीर्ष रक्षा कंपनियों की सामूहिक विक्री 2018 में 6.9 प्रतिशत घटकर जितने अरब अमेरिकी डॉलर रह गई - 5.9 अरब अमेरिकी डॉलर
- जिसके द्वारा किया गया ट्रॉफी भारत का 'गोल्डन ट्रॉफी 2019' कहा गया है - नरेंद्र मोदी

# हिमाचल सामाज्य शान

- ऐतिहासिक यूनेस्को हेरीटेज शिमला कालका रेलवे पर वर्ष 2020 तक कितने किलोमीटर प्रतिशंका के स्पीड से ट्रेने दौड़ेंगी - 30 किलोमीटर प्रतिशंका के हिसाब से
- हिमाचल प्रदेश पुलिस के स्थापना दिवस पर कितने पुलिस अधिकारियों को डीजीपी डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया गया है - 64 को
- हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाएगी - 11 हजार रुपये
- हाल ही में शिमला के सुन्नी में सीमेंट फ्लांट लगाने के लिए किस ग्रुप को लेटर ऑफ इंटेट जारी किया गया - डालिमिया ग्रुप
- मंडी जिला के सरकारी तहसील के तहत श्री नवाही देवी मंदिर को सरकार किस नियम के तहत अधिग्रहण करने का निर्णय लिया - हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक स्थान एवं पूर

# हिमाचल ओल्ड एज पेंशन योजना



हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के वृद्ध लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की है। ये योजना राज्य के सभी जाति के लोगों के लिए है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राज्य के वे लोग जिनकी उम्र 60 साल से

उपर है, उनके लिए राज्य सरकार हिमाचल ओल्ड एज पेंशन योजना दे

रही है। इसके साथ ही सरकार की ओर से अपंग राहत भत्ता योजना भी

चलाई जा रही है।

द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे अपने घर के अथवा किसी अन्य बुजुर्ग को इसका लाभ पहुंचा सकते हैं, और अपंग राहत भत्ता कैसे हासिल किया जा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए आपको कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना 2019-20, हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना 2019-20, हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना औनलाइन आवेदन, विडो पेंशन इन हिमाचल प्रदेश, बुढ़ापा पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश की पूरी जानकारी आपको इस आर्टिकल के माध्यम से प्राप्त होगी। इस योजना के तहत जिन बुजुर्गों की आयु 60 साल है या फिर 60 से उपर है उन्हें सरकार द्वारा अंतर्गत 60 साल से 69 साल की आयु के लोगों को हर महीने 1300 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य सरकार द्वारा राज्य के बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ताकि वे कुछ हद तक आत्मनिर्भर बन सके। इसी उद्देश्य से हिमाचल के बुजुर्गों को सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू की गई है।

सरकार द्वारा प्रदेश में बुजुर्गों के लिए HP Old Age Pension Yojana शुरू की है। इससे पहले कुछ एक राज्यों में बुजुर्गों की हालत बहुत खराब थी। उनके अपने बच्चे उन्हें बोझ समझने लगते थे। जब कोई व्यक्ति कमाना छोड़ देता है और चारपाई पकड़ लेता है तो वह पूरे परिवार को खलने लगता है। बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने पूरे देश में वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की है।

इस योजना के तहत बुजुर्गों को प्रतिमाह पेंशन दी जाती है इसी बजह से अब उन्हें अपने बच्चों या फिर परिवार के किसी अन्य सदस्य पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू होने के बाद वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों की संख्या धट्टी नजर आ रही है। इस योजना के तहत देश के सभी बुजुर्ग आत्मनिर्भर हो गये हैं।



## चलो, उनका साथ दे जिन्होंने जिंदगी दिखाई !

### कौन हैं पेंशन के पात्र

- हिमाचल राज्य सरकार द्वारा उन बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन योजना दी जाएगी जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो।
- जिन लोगों के देख रेख और रहने सहने की सुविधा न हो, इसके अलावा जो बुजुर्ग घर से बेघर है या फिर उन्हें खाने पीने की सुविधा नहीं मिल रही है तो उन लोगों को भी सरकार द्वारा ये पेंशन दी जाएगी।
- ये पेंशन योजना केवल उन्हीं बुजुर्गों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 35,000 से ज्यादा न हो।

हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको जिन दस्तावेजों को आवश्यकता है :- आधार कार्ड व कुछ अन्य दस्तावेज शामिल हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार के पास आधार कार्ड का होना बेहद अनिवार्य है। सरकार की ओर से जिन बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन योजना की राशि दी जाएगी यह उनके खाते में जाएगी।

ऐसे में उम्मीदवार के पास खुद का बैंक खाता होना जरूरी है। सरकार ने ये योजना इसलिए शुरू की है ताकि जिस बुजुर्ग को ये पेंशन दी जा रही है उसकी राशि उसके ही बैंक खाते में रहे और उसे कोई दूसरा न ले पाए। योजना में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए उम्मीदवार के पास 2 पासपोर्ट साइज के फोटो होने चाहिए। जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा है और वे योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए अपना आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है यदि जबकि 70 साल और इससे अधिक की उम्र वाले लोगों को आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है।

वृद्धावस्था पेंशन	
1	प्रार्थी 60 वर्ष या अधिक आयु का हो
2	प्रार्थी जिनकी परिवार सहित वार्षिक आय 35,000 से अधिक न हो चाहे लड़के अलग ही रहते हों
3	सम्बन्धित ग्राम सभा से प्रस्ताव
4	परिवार नकल
5	आधार कार्ड
6	बैंक खाता
7	दूसरी श्रेणी पात्रता
8	प्रार्थी 70 वर्ष या अधिक आयु का हो
9	शपथ पत्र जिसमें यह वर्णित हो कि प्रार्थी को किसी प्रकार की पेंशन नहीं लगी है
10	परिवार नकल
12	इस पेंशन हेतु ग्राम सभा प्रस्ताव एवं आय प्रमाण पत्र देना आवश्यक नहीं है

### हिमाचल प्रदेश सरकार पेंशन योजना राशि

अंतर्गत 60 साल से 69 साल की आयु के लोगों को हर महीने 750 रुपये दिए जायेंगे। इसके अलावा जिन लोगों की उम्र 70 साल या फिर इससे अधिक है उन्हें 1300 रुपये प्रतिमाह दिए जायेंगे।



### ऐसे करें आवदेन

सरकार द्वारा अब हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गयी है। इसके साथ ही आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप औनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑफिस जाना होगा। आवेदन करने के लिए आपको एक आवेदन फॉर्म लेना होगा।

यह फॉर्म आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर HP Old Age Pension Yojana Form PDF पर क्लिक करके डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए आपको बुढ़ापा पेंशन योजना का प्रमाण पत्र लेना होगा। जो की आप अपने ग्राम पंचायत या नगर निगम से बनवा सकते हैं। इसके बाद आपको पंचायत सेकेटरी के पास इस फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म में पूरी जानकारी सही ढंग से भरने के बाद इसे जिला कल्याण कार्यालय में जाकर इसे जमा करा होता है। आपके दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच होने के बाद आपको पेंशन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

### हिमाचल सरकार द्वारा वृद्ध नागरिकों के लिए खोले गए वृद्धाश्रम

अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने वृद्ध नागरिकों के कल्याण के लिए प्रदेश भर में कई जगह वृद्धाश्रम भी खोले गए हैं। वृद्धाश्रम इसी विभाग द्वारा अकेले, बेसहारा वृद्ध नागरिकों के लिए संचालित किया जा रहा है। इन वृद्धाश्रमों का संचालन स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। वृद्ध नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम प्रदेश के प्रमुख नगर-दाली (धर्मशाला), बसन्तपुर (शिमला), भंगरोटू (मण्डी), कलाथ (मनाली) में खोले गए हैं। इसके साथ ही केन्द्र सरकार की अनुदान सहायता से एक वृद्धाश्रम कदेनदार्यान मैमोरियल वैलफेर योग्याई ग्रामों (स्पिटि) जिला लाहौल स्पिटि में भी संचालित किया जा रहा है। इन वृद्धाश्रमों में वृद्ध नागरिकों को मुफ्त रहन-सहन, भोजन, चिकित्सा तथा मनोरंजन आदि की सुविधा दी जाती है।



### अपंग राहत भत्ता

उद्देश्य अपंग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। पात्रता ऐसे अपंग व्यक्ति जिन्हें "व्यक्ति जिनमें अक्षमताएं हैं (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण, एवं पूर्ण भागीदारी)" अधिनियम 1995 की धारा 2 में अपंगता की परिभाषा के अनुसार गठित चिकित्सा बोर्ड से जिन्हें 40 प्रतिशत या इस से अधिक स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तथा जिनके कोई भी व्यस्क बच्चे न हो तथा वार्षिक आय समस्त स्वोतों से 35,000/- रु० से अधिक न हो।

चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रतिशतता प्रमाण-पत्र चाहे वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के मूल्यांकन तथा प्रमाणित करने हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बहु-विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक प्रमाणित की गई हो, अपंग राहत भत्ता स्वीकृति हेतु मान्य है। मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को तथा 70 प्रतिशत या इससे अधिक अपंगता वाले व्यक्तियों को जारी है। सहायता 40 से 69 प्रतिशत अपंगता वाले पेंशनरों को 750/- रु० प्रतिमाह। 70 प्रतिशत या इससे अधिक अपंगता वाले पेंशनरों को 1300/- रु० प्रतिमाह।



70 वर्ष या इससे अध

# 'फेम इंडिया' स्कीम, क्या है मकसद और इसका फायदा

देश में कलीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने 'फेम इंडिया' स्कीम लांच किया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स (फेम) स्कीम को अप्रैल, 2015 में लांच किया। सरकार की योजना इस स्कीम के जरिए साल 2022 तक देशभर में 60-70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल वाहनों को दौराने की है। इससे करीब 950 करोड़ लीटर पेट्रोल एवं डीजल की स्वापत में कमी आएगी। जिससे इस पर रखर्च होने वाले 62 हजार करोड़ रुपए की भी बचत होगी। इस स्कीम को लागू करने का मकसद पॉल्यूशन को कम करना और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी लाना है।



## क्या है 'फेम इंडिया' स्कीम

दरअसल सरकार की योजना 'फेम इंडिया' के तहत साल 2022 तक देश को पॉल्यूशन मुक्त बनाने की है। जिसके लिए सरकार ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यानी (फेम) इंडिया स्कीम बनाई है। इसका मकसद कस्टमर को सस्ते दामों पर हाइब्रिड व इलेक्ट्रिकल वाहन उपलब्ध कराना है। जिसके तहत डीजल और पेट्रोल की जगह हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल दोपहिया वाहन, कार, तिपहिया वाहन और हल्के व भारी कमर्शियल वाहनों के लिए देशभर में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। साथ ही इसका उत्पादन भी भारत में किया जाएगा। इसके अलावा इस स्कीम को सफल बनाने के लिए दोपहिया, तिपहिया वाहन और कार पर छूट भी देगी। सरकार इस स्कीम के तहत पहले दो साल में 795 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके लिए 2015-16 के बजट में 75 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जिसमें से 30 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं।

## यह स्कीम इन शहरों में होगी लागू

फेम इंडिया स्कीम देश के प्रमुख मेट्रोपोलिटन सिटी दिल्ली एनसीआर, ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलुरू, हैदराबाद और अहमदाबाद में लागू किया जाएगा। इसके अलावा साल 2011 की जनगणना के अनुसार जिन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा होगी वहाँ भी इसको लागू किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों के शहरों में भी यह स्कीम लागू होगा। वहाँ, राज्य यदि चाहें तो इसे अपने अन्य शहरों में भी लागू कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत वाहनों पर छूट इस स्कीम को सफल बनाने के लिए सरकार कस्टमर को हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदने पर छूट देगी। जिसमें टू-व्हीलर स्कूटर पर 1800 से लेकर 22 हजार रुपए, मोटरसाइकिल पर 3500 से 29 हजार रुपए, थी-व्हीलर ऑटोरिक्षा पर 3300 से 61 हजार रुपए, फोर-व्हीलर कार पर 11000 से

1 लाख 38 हजार रुपए व हल्के कमर्शियल व्हीकल्स पर 17000 से 1 लाख 87 हजार रुपए और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स बस पर 30 लाख से 66 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी।

## इस स्कीम का क्या है फायदा

सरकार का मकसद साल 2022 तक देश को पॉल्यूशन मुक्त बनाना है। जिसके लिए सरकार फेम इंडिया को बढ़ावा दे रही है। ताकि विदेश से होने वाले पेट्रोल और डीजल के आयात को कम करना और इस पर खर्च होने वाले विदेशी मुद्रा का बचत भी करना है। जिससे सरकार को तकरीबन 62 हजार करोड़ रुपए के बचत होने की उम्मीद है। इस स्कीम के जरिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग से सीधे तौर पर 60 से 65 हजार

डीजल एवं पेट्रोल चालित गाड़ियों से फैलने वाला धुआं है। इस भीषण प्रदूषण से वातावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा वर्ष

2015 में फेम इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का पहले चरण वर्ष 2015-2018 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और देश में मेक इन इंडिया के तर्ज पर इलेक्ट्रिक कारों एवं दो पहिया हाइब्रिड वाहनों के निर्माण को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई थी। इस योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ ही वार्षिक 60 हजार करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी।

## फेम इंडिया योजना का क्रियान्वयन

इस योजना का पहला चरण वर्ष 2015 से 2018 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और देश में मेक इन इंडिया के तर्ज पर इलेक्ट्रिक कारों एवं दो पहिया हाइब्रिड वाहनों के निर्माण को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई थी। इस सत्र के अंतर्गत फेम इंडिया योजना के लिए रुपए 795 करोड़ रुपए का समर्थन मिल चुका है। इस योजना का दूसरा चरण आगामी पांच सालों तक चलने के प्रस्ताव को निर्धारित किया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दूसरे चरण के अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन एवं वाणिज्य उपयोग के लिए नवीन उर्जा से चलने वाले वाहनों तथा तीव्र गति से चलने वाले दो पहिया वाहनों पर केन्द्रित होगा। इस चरण के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 9,381 करोड़ रुपए प्रस्ताव पास किया जा सकता है।

## फेम इंडिया योजना से लाभ

इस योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन से वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।

एक अनुमान के अनुसार 60 हजार करोड़ ईंधन की बचत हो सकेगी। सरकार इलेक्ट्रिक चालित वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर 1.38 लाख रुपए और दो पहिया हाइब्रिड वाहनों के खरीद पर 29 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रस्ताव पारित करेगी।

फेम इंडिया योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देश में 60-70 लाख हाइब्रिड दो पहिया वाहन और इलेक्ट्रिक कार को सड़क पर चलाने की योजना है।



लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही अप्रत्यक्ष तौर पर हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल वाहनों से जुड़े हुए पुर्जा जैसे बैट्री, मोर्टस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के निर्माण आदि से भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यानी कि इस स्कीम से कुल मिलाकर इससे 2.50 से 3 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वहाँ, सरकार का मकसद इस स्कीम के जरिए मेक इन इंडिया और नेशनल ट्रांस्पोर्ट पॉलिसी को बढ़ावा देना है।

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश में बढ़ रहे प्रदूषण पर काबू पाने के लिए वर्ष 2015 में फेम इंडिया स्कीम के तहत फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग आफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया की शुरुआत किया गया था।

## फेम इंडिया योजना का उद्देश्य

देश में खासतौर से महानगरों में प्रदूषण के अन्य कारणों में से मुख्य कारण

## स्त्री स्वाभिमान योजना

**Behind Every Successful Woman is Herself**

स्त्री स्वाभिमान योजना 27 जनवरी, 2018 को लॉन्च की गई। इसका उद्द्यान केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा CSC महिला वीएलई (Village Level Entrepreneur) कार्यक्रम के दौरान किया गया।

- यह योजना Ministry of Electronics and Information Technology के अधीन है।
- स्त्री स्वाभिमान योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं को Eco Friendly सैनिटरी नैपकिन वितरित करना है।
- खासकर ग्रामीण इलाकों की लड़कियों और महिलाओं को।
- यह सैनिटरी नैपकिन महिलाओं को बहुत ही कम मूल्य पर दिए जाएंगे।
- CSC (Common Service Center) में देश में बहुत सी जगहों पर छोटी-छोटी निर्माण के लिए यूनिट्स लगाई जाएंगी।
- जिसमें अधिकतर महिलाएं ही शामिल होंगी।
- इनमें सैनिटरी नैपकिन बनाए जाएंगे जो इको फ्रेंडली होंगे और कम मूल्य पर बेचे जाएंगे।
- इसे बनाने की प्रक्रिया भी बहुत सरल और परेशानी मुक्त है।

- स्त्री स्वाभिमान के अंतर्गत देशभर में निर्माण यूनिट्स लगाई जाएंगी जिससे 8 से 10 महिलाओं को रोजगार भी दिया जाएगा।
- इससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
- महिलाओं और लड़कियों को कम मूल्य पर सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे।
- यह सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने में आसान और सुरक्षित होंगे।
- ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने के फायदे बताए जाएंगे।
- महिलाओं में मासिक धर्म के समय स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में बढ़ोत्तरी होगी।
- मासिक धर्म के समय सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी।
- VLE सरकारी स्कूल की सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन प्रदान करेगी।
- इस योजना से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी जाएगी।
- यह योजना CSC के माध्यम से देश भर तक पहुंचाई जा रही है।





20/20 Year

# MISSION RIEV

## Ruralising India- Empowering Villages

INSTITUTE FOR INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT  
By pass Road, Shanan, Sanjauli, Shimla H.P. 171006 India, Web: missionrev.in , web: iirdshimla.org



कि दुनिया देखती रह जाए



### IIRD Holiday's List

S No	Name of Holiday	Date	Day	S No	Name of Holiday	Date	Day
1	Republic Day	26 January	Sunday	7	Independence Day	15 August	Saturday
2	Mahashivratri	21 February	Friday	8	Mahatma Gandhi B'day	02 October	Friday
3	Holi	10 March	Tuesday	9	Dusshera	25 October	Sunday
4	Himachal Day	15 March	Wednesday	10	Diwali	14 November	Saturday
5	Janamashtami	12 August	Wednesday	11	Guru Nanak B'day	30 November	Monday
6	Raksha Bandhan	03 August	Monday	12	Christmas	25 December	Friday

### सार्वजनिक सरकारी अवकाश

पूर्ण राजत्व दिवस	25 जनवरी
गणतंत्र दिवस	26 जनवरी
गुरु रवि दास जयंती	09 फरवरी
महा शिवारात्री	21 फरवरी
होली	10 मार्च
रामनवमी	02 अप्रैल
गुड फ्राइडे	10 अप्रैल
डा.बीआर अंबेदकर जयंती	14 अप्रैल
हिमाचल दिवस	15 अप्रैल
परशुराम जयंती	25 अप्रैल
बुद्ध पूर्णिमा	07 मई
इद-उल-फितर	25 मई
संत गुरु कबीर जयंती	05 जून
इद-उल-जुहा (बकरीद)	01 अगस्त
जन्माष्टमी	12 अगस्त
स्वांत्रता दिवस	15 अगस्त
मुहर्म	30 अगस्त
महात्मा गांधी जयंती	02 अक्टूबर
दशहरा	25 अक्टूबर
महर्षि बाल्मीकी जयंती	31 अक्टूबर
दिवाली	14 नवम्बर
गुरु नानक जयंती	30 नवम्बर
किसमस-डे	25 दिसम्बर

### वैकल्पिक अवकाश

नववर्ष दिवस	01 जनवरी
लोहड़ी	13 जनवरी
बसंत पंचमी	30 जनवरी
मकर संक्रान्ति	15 फरवरी
स्वामी दयानन्द सरस्वती जयंती	18 फरवरी
महाद्वारा जयंती	06 अप्रैल
ईस्टर-डे	12 अप्रैल
बैसाखी	13 अप्रैल
महा अष्टमी	24 अक्टूबर
गोवर्धन पूजा	15 नवम्बर
गुरु तैगबाहुदुर शहीदी दिवस	24 नवम्बर
किसमस संध्या	24 दिसम्बर

### महिला कर्मचारियों के लिए अवकाश

रक्षा बंधन	03 अगस्त
करवाचौथ	04 नवम्बर
भाईदूज	16 नवम्बर

### द रीव टाइम्स

संस्थापक: डॉ ए.ल.सी. शर्मा  
प्रकाशक: आईआईआरडी काम्पलेक्स, बाईपास रोड शनान, सन्जौली शिमला-6 हि.प्र.  
द रीव टाइम्स के लिए मुद्रक प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस, सायबू निवास समीप सेक्टर-2, बस स्टैंड, मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुक्ति संपादक: हेम राज चौहान

फोन नं.: 0177 2640761  
आ.एन.आई.रिफ्रेंस नं. 1328500  
टाइटल कोड : HPBIL00313  
पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं. HP/129/SML/2019-2021  
E-mail : hem.raj@iirdshimla.org  
Website : www.therievtimes.com